डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी
रिसर्च फाउंडेशन

हारता कोरोना विजय की ओर भारत

संपादन

आदर्श तिवारी

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

रिसर्च टीम

अभय सिंह

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

मनुजम पांडेय

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

डिजाइन

अजित कुमार सिंह

मई-जून 2020

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-23005850

भूमिका

आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। चूंकि कोरोना समस्त मानवजाति के लिए बिल्कुल अलग तरह की समस्या है, इसलिए इससे निपटने का कोई ठोस उपाय किसी को ज्ञात नहीं है। दो गज की दूरी व मास्क का उपयोग यही कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनसे लोग खुद को वायरस से कुछ हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। गौरतलब है कि विश्व के ज्यादातर देश इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, लेकिन इस लिहाज से अगर भारत की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में देश काफी हद तक सफल रहा है। कोरोना वायरस से देश में स्वस्थ होने की दर आज लगभग 63 प्रतिशत पर पहुँच गई है। 1,13,07,002 टेस्ट अबतक पूरे देश में हो चुके हैं तथा भारत में मृत्यु दर 2.72 प्रतिशत का होना यह दर्शाता है कि हम इस जंग में अग्रणी भूमिका में हैं। ज्ञातव्य हो कि इस कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलानी हो या फिर गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना हो, केंद्र सरकार द्वारा एक के बाद दूरदर्शी निर्णय लिए गए। इसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिये आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने का काम भी केंद्र सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों की सराहना वैश्विक पटल हो रही है। हर किसी के मन में रिकवरी रेट में प्रतिदिन हो रहे सुधार, आर्थिक तंत्र को गतिमान करने के पीछे का कारण जानने की उत्सुकता है. इस बुकलेट के माध्यम में हम कैसे कोरोना को हराते जा रहे हैं उसका तथ्यात्मक और प्रमाणिक विश्लेषण पाठकों को पढ़ने को मिलेगा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट एवं वैचारिक पोर्टल नेशनलिस्ट ऑनलाइन पर मई और जून महीने में प्रकाशित लेखों के साथ-साथ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों को संग्रह करके इस ई-बुकलेट का प्रकाशन कर रहा है। इस संकलन में लिए गए लेखों के लिए संस्थान लेखकों एवं समाचार पत्रों के प्रति आभार ज्ञापित करता है।

कोविड-19 अपडेट -

लॉकडाउन के सराहनीय निर्णय से हुआ लाभ –

- लॉक डाउन का लाभ यह हुआ कि कोरोना के सामुदायिक प्रसार की तीव्रता को नियंत्रित करने में दुनिया की तुलना में भारत को अधिक कामयाबी मिली.
- लॉकडाउन के तीन फायदे, पहला- संक्रमण की चेन टूटी, दूसरा- डबलिंग रेट घटा, तीसरा- टेस्टिंग बढ़ी.
- लॉकडाउन के कारण कोविड-19 से संक्रमण के 14 से 29 लाख तक मामले कम किए जा सके जबकि 37 हजार से 78 हजार के बीच लोगों की जिंदगी बचा ली गई.
- भारत में रिकवरी रेट और मृत्यु दर
- भारत में रिकवरी रेट बढ़ कर हुआ 62.78%
- मृत्यु दर घटकर 2.72 प्रतिशत हुई
- सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक हुए लोगों की संख्या 1.75 गुना अधिक है; ठीक हुए लोगों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 2 लाख से अधिक हुआ।
- भारत में प्रति दस लाख पर मामले (538) तथा प्रति दस लाख पर मृत्यु (15) है जो क्रमशः 1453 और 68.7 के वैश्विक औसत की तुलना में निम्नतम में से एक है।
- भारत में प्रति मिलियन आबादी में 15.31 मौतें हुई हैं, जिसके आधार पर मृत्यु दर 2.75% है, जबकि विश्व स्तर पर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 68.7 मौतें हुई हैं।
- ब्रिटेन में प्रति दस लाख आबादी पर कोविड से मरने वालों की संख्या 651.4 है, जबकि स्पेन, इटली, फ्रांस और अमेरिका में यह आंकड़ा क्रमशः 607.1, 576.6, 456.7 और 391.0 है।

लगातार बढ़ती अस्पतालों की संख्या –

कोरोना जब भारत में आया उसवक्त कोरोना के इलाज के लिए हमारे पास मात्र एक अस्पताल था.

आज देश में 1218 समर्पित कोविड अस्पताल, 2705 समर्पित कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और 10,301 कोविड देखभाल केंद्र हैं।

41 हजार से अधिक आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती केंद्र विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान सर्व-जन और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहे हैं।

टेस्टिंग लैब की संख्या में हो रही लगातार बढोत्तरी-

» कुल लैब संख्या- 1,180

» सरकारी लैब -841

» प्राइवेट लैब -339

टेस्टिंग क्षमता –

- टेस्टिंग क्षमता बढ़कर लगभग तीन लाख प्रतिदिन हो गई है-
- अबतक 1,13,07,002 नमूनों की जांच की जा चुकी है।

(आंकड़े 10 जुलाई 2020 तक)

विषय सूची

1.	Regaining 'Aatma Nirbhar Bharat' **- Dr. Anirban Ganguly**	**8**
2.	Unprecedented Crisis, India's Unparalleled Global Response **- Amb Kanwal Sibal**	**13**
3.	Decongesting cities for coping with Coronavirus **- Prof. Ila Patnaik**	**17**
4.	Aatma Nirbhar Bharat **- Brig Anil Gupta**	**22**
5.	PM Modi's Clarion Call for Atmanirbhar Bharat Abhiyan: A Game Changer for India's Resurgent Future **- Pathikrit Payne**	**28**
6.	UP, not Kerala deserves to be lauded as the Model Covid Control State of India **- Debjani Bhattacharyya**	**41**
7.	चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास है आत्मनिर्भर भारत अभियान **- हर्षवर्धन त्रिपाठी**	**48**
8.	लॉक से अनलॉक का औचित्य **-शिवानंद द्विवेदी**	**55**
9.	रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती से आमजन को मिलेगी राहत **- सतीश सिंह**	**58**
10.	कोरोना संकट : गरीबों के हितों के साथ-साथ राज्य के विकास को लेकर भी सक्रिय है योगी सरकार **- डॉ दिलीप अग्निहोत्री**	**60**
11.	अब जल शक्ति घर लौटे कामगारों का बनेगा आधार **- नेशनलिस्ट टीम**	**63**
12.	मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे, वो कांग्रेसी सरकारों के एजेंडे में कभी था ही नहीं **- रमेश कुमार दूबे**	**65**

13.	विज्ञान ही नहीं, अध्यात्म के जरिये भी कोरोना से लड़ रहा भारत - **नीलम महेंद्र**	**68**
14.	कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन का महत्व विपक्ष भले न समझे, मगर आम लोगों ने बखूबी समझ लिया है - **नवोदित सक्तावत**	**71**
15.	गेम चेंजर साबित हो सकता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान - **प्रहलाद सबनानी**	**73**
16.	कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार द्वारा समय के साथ लिए गए निर्णयों को समझने की आवश्यकता है - **सन्नी कुमार**	**76**
17.	बस प्रकरण : लोगों की 'सेवा' का दावा कर रही कांग्रेस की मंशा पर उठते हैं गहरे सवाल - **अनुराग सिंह**	**80**
18.	'सशक्त नारी, समर्थ समाज' के पथ पर अग्रसर योगी सरकार - **खुशबू गुप्ता**	**83**
19.	कोरोना संकट के दौर में यूपी सरकार ने जीता जनता का दिल, मुद्दाविहीन हुआ विपक्ष - **प्रणति तिवारी मुखर्जी**	**87**
20.	कोरोना संक्रमण के आगे दिल्ली- सरकार ने टेके घुटने, अमित शाह ने थामी कमान - **नेशनलिस्ट टीम**	**90**
21.	केंद्र सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही कोरोना का सामना करने के लिए पूरे देश को किया एकजुट - **ए. सूर्यप्रकाश**	**92**
22.	कोरोना संकट से निपटने में CM योगी के कौशल की सराहना PM से लेकर पाकिस्तान तक कर रहे - **सद्गुरु शरण**	**95**
23.	आत्मनिर्भरता की बुनियाद - **जयंतीलाल भंडारी**	**97**
24.	कोरोना काल में बैंकों की भांति और उपयोगी साबित हुए डाकघर - **कपिल अग्रवाल**	**100**
25.	**कोरोना काल के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 50 हजार करोड़ डॉलर हो जाना सुखद आश्चर्य - डॉ. सुशील कुमार सिंह**	**102**

Regaining 'Aatma Nirbhar Bharat'

Dr. Anirban Ganguly

A contextual look at the background of the ideal of 'Aatma Nirbhar Bharat', of past glories and devastation of India's traditional industrial base at the hands of greedy, exploitative colonisers.

The ideal of Aatma Nirbhar Bharat has long guided and driven our quest for political, cultural and intellectual freedom. It is therefore symbolic that at a time when India is on the cusp of a civilisational leap when she is determined to play her role, strive for her interests and secure her global position, that this clarion call has once more been given by a leader who has worked to fundamentally reshape India in the last six years.

Against this backdrop, in our quest for comprehending the philosophy of 'Aatma Nirbharta' — self-dependence — in the Indian context, it will be useful to see how that self-dependence was decimated. The subjugation of India also paved the way for an era of exploitation. From a self-dependent polity, India gradually became a colony for extraction. With physical extraction was added the continuous attempt to deconstruct India — Bharat, intellectually and socially.

By 1818, Colonel Alexander Walker who had served in the country for decades and whose sympathetic and detailed accounts of India of

the epoch enable us to absorb and surmise the positives and strengths of Indian society which was fast depleting or disappearing under the duress of occupation and exploitation wrote of how six decades of exploitative British rule had begun breaking the fundamentals of Indian society. 'We have left wounds in every quarter', wrote Walker, 'and produced discontent everywhere, the confidence which was once reposed in our moderation and justice is gone. We have made use of treaties, contracted solely for protection, as the means of making violent demands… Every individual almost above the common artisan and labourer suffers by our system of government.' In areas which were under the direct subjection of the colonial government, Walker noted, 'or controlled by its influence, the inhabitants were reduced to wretchedness and penury.'

In another letter in 1820 to James Mill, the British historian who never set foot in India and yet dominated the creation of the Indian narrative in the West, Walker described how British rule had completely ruined and degraded India's wealth and inflicted an exploitative relation which was both destructive and deadly:

'It has been computed that Nader Shah carried out of India 30 million sterling, this was besides all that was consumed, destroyed and plundered, but the spoils which we have brought from India probably exceed a hundredfold all that our predecessors have taken by fits and starts. It would be a curious calculation to ascertain the amount of the wealth which has been brought by the Company and individuals from India… The drains which we have made from India have been less violent than the exactions of other conquerors but they have perhaps in their operations proved more destructive and deadly to the people. We have

emptied gradually, but the pitcher has gone constantly to the well…'

In his eminently readable 'The Theft of India: The European Conquests of India – 1498-1765', British historian and archivist, Roy Moxham, mentions how after the defeat at Plassey, 'seventy-five boats were loaded up, each carrying a large chest containing Rs 100.000' and 'headed down the river to Calcutta, escorted by the navy, and serenaded by music and drum…' Moxham computes that 'altogether this came to nearly a quarter-million pounds sterling. In all, the equivalent of one years' total revenue of Bengal found its way to Britain.'

From being a country of producers, we systematically turned into a country that supplied raw materials. Edmund Burke perhaps described this best when, in course of his famous speech during the debate on the 'East India Bill' in December 1783, he said that "every rupee of profit made by an Englishman is lost forever to India." A look at Burke's speech makes one realise how we gradually slipped away from a situation of self-dependence and surplus to a level of subjection, scarcity and deprivation. It is a speech that one must keep revisiting. Describing the people of India as a people who have been for ages "civilised and cultivated, cultivated by all the arts of polished life, whilst we were yet in the woods", Burke spoke of their industrial prowess, their rich and varied craftsmanship and the entrepreneurial spirit that drove them: "merchants and bankers, individual houses of whom have once vied in the capital with the Bank of England whose credit had often supported a tottering state, and preserved their governments in the midst of war and desolation, millions of ingenious manufacturers and mechanics, [sic] millions of the most diligent, and not the least intelligent, tillers of the earth…" It was critical

thus that the handling of India needed to be done delicately, instead, "it has been handled rudely", argued Burke.

In his richly documented and fascinating autobiography, 'Life and Experiences of a Bengali Chemist'. Acharya Prafulla Chandra Ray, for instance, has deeply delved into the destruction of Indian industry, its starvation, its exploitation and marginalisation. In the backdrop of the PM Modi's call for Aatma Nirbhar Bharat, Acharya Ray's magnum opus may be a useful guide for us to better comprehend our degradation and aspirations. He remains one of the earliest and most creative voices of our quest for Aatma Nirbahar Bharat. Ray refers to the 'Plassey Drain' a term used to describe the plunder of India post-Plassey. The 'total drain to England during the period 1757 to 1780,' writes Acharya Ray, 'often named the Plassey Drain, is put down at 38 million pounds sterling.'

In his once widely read and cited opus, 'Economic Annals of Bengal' (1926), JC Sinha of Dacca University, explains in detail the 'Plassey Drain' which was mainly about the continuous outflow of a huge volume of bullion to England from Bengal. Writes Sinha, of the 'Plassey Drain', 'Even if it was a few million pounds less, it must have been a very heavy burden on the people of Bengal, much heavier at that time than it would be at the present day because the purchasing power of the rupee was then at least five times as high.'

Sympathetic British journalist and writer, William Digby, who had done pioneering work in exposing the British engineered cycles of famine in India, for example, in his 'Prosperous British India: A Revelation from Official Records' (1901), speaks of 'the drain of Indian treasure varying from five hundred to one thousand million pounds to England between

Plassey [1757] and Waterloo [1815].' Within a quarter of a century of Clive having described Murshidabad, in Bengal as 'extensive, populous and rich as the city of London', writes Acharya Prafulla Chandra Ray, 'the very same Murshidabad resembled a sucked orange and presented a scene of ruin and desolation, thanks to the Plassey Drain.'

But this gradual and rude descent from the status of overflowing-plenty into an exploited, scarcity imposed, violently exacted, supplier status, could not crush or subjugate our innate resilience. It rather gave rise to three dimensions of action in us. One was the actual material, the quest for regenerating and recreating India's traditional industrial base, adapting and adopting newer methods and technologies of invention and production — the movement for swadeshi — looking for self-dependence and sustenance from our core strengths. The second was dimension was an ideational quest for self-dependence and an intellectual, cultural self-estimation and the third was a renewed look at the world in which India's civilisational message could radiate and become once more the influencer. These three fundamental directions would shape our quest for Aatma Nirbhar Bharat.

(The writer is the Director of Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation. Views expressed are personal)

Unprecedented Crisis, India's Unparalleled Global Response

Amb Kanwal Sibal

With the Wuhan virus pandemic enforcing a complete lockdown of the country for several weeks followed by a partial easing, the normal functioning of the Government, and indeed the society at large, was disrupted. Other parts of the Government, especially the Ministry of External Affairs (MEA), had its share of challenges on the diplomatic front, which it has discharged commendably under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.

The immediate challenge was to obtain the cooperation of foreign embassies in the country to observe the lockdown, function with reduced staff, and accept severe restrictions on plying of diplomatic vehicles on the roads, and so on. Some missions were unhappy with the restrictions, arguing they needed more personnel and vehicle passes to handle the several flights they were organising to evacuate their citizens from India. It goes to the credit of the MEA that in the most intensive phase of the lockdown, it handled the requirements of the mission with firmness combined with flexibility to the point that many missions have lauded the excellent cooperation they received from the Ministry. The MEA facilitated the evacuation of 60,000 nationals from 70 countries. As the situation has evolved, a 100-member COVID cell is now functioning in the Ministry.

More importantly, bringing back the Indians stranded abroad posed a

problem with the lockdown and a ban on international flights. Some nationals were evacuated early on from Wuhan, Iran, and Japan. Subsequently, in the first phase of the Vande Bharat mission, 7,000 Indians were brought back directly to secondary airports in the States as a part of control measures. This administrative arrangement required a great deal of coordination between the MEA, our missions abroad and State Governments. In the second mission, 30,000 Indians from 31 countries will be brought back home. Altogether 200,000 Indian nationals will be repatriated. Those who may have to wait for evacuation are from countries such as Peru, Serbia, Bulgaria etc. are being given full assistance by the Indian missions, including mobilising support for them by local organisations. At the senior level, the MEA has appointed one Additional Secretary each in important states receiving evacuees for single-point coordination.

At a higher diplomatic level, the MEA has played a crucial role in PM's initiative to hold discussions within the framework of SAARC, the G20 and the virtual Non-Aligned Summit. Not only that, even the Prime Minister has personally spoken to several world leaders, apart from the EAM holding several virtual meetings with the Foreign Ministers of the Quad plus group, and that of BRICS and the SCO, not to mention individual Foreign Ministers. The Foreign Secretary has been intimately involved in Indo-Pacific dialogue on the situation arising from the virus with a focus on health and food supply issues, besides talking to Russia and the EU on COVID-related cooperation.

This active diplomacy has been necessary in view of the unprecedented international crisis caused by the Wuhan virus that requires a multilateral as well as a plurilateral efforts to assess its consequences, discuss the need for an independent probe into its origin, the strengthening of the WHO to

deal with such pandemics in the future by developing new protocols, the necessity of working together to minimise the devastating economic impact of this pandemic by avoiding protectionism and coordinating to the extent possible the stimulus measures taken by individual countries. In the absence of international leadership because of internal politics in the US around the handling of the pandemic by President Trump, China's aggressive posturing and resort to threats against those who demand a probe into China's handling of the epidemic when it first erupted in Wuhan and its culpability in its delay to take steps that could have prevented it from becoming a pandemic, and the disarray in Europe caused by the spread of the virus there, Prime Minister at his level, supported by the MEA has tried to fill that leadership void with visible success.

As part of India's leadership role, it made available medicines like Hydroxychloroquine and Paracetamol in large quantities to numerous countries to meet their domestic requirements in a crisis situation. These have been made possible after a meticulous study of domestic need in a worst-case scenario and the surplus available for meeting the needs of other countries either commercially or a grant basis. This has been part of India's imaginative medicine diplomacy, which has generated positive sentiments towards India, with many world leaders conveying their gratitude to India. India also met the request for Rapid Response Teams to deal with the virus from countries such as Kuwait, Seychelles and Comoros, for example, and has sent medicines to Bahrain. In the Gulf, while India would have to cope with numbers coming back, make a list of their skills for use domestically, there is a surge in demand for health workers forwhich retired personnel from the armed forces could be mobilised. 15,000 Indian nationals working in cruise

liners would also need to brought back, which is another organisational challenge for the MEA.

Under instructions from the Prime Minister to our heads of missions, our missions have been pro-active in sourcing medical equipment, make openings for our participation in R&D for medicines or development of a vaccine for combatting the virus, with the result that any success in this regard will have some Indian participation, which, in turn, will facilitate more access to breakthroughs. The MEA has been active in procuring critical components from China for N-95 masks, Hydroxychloroquine and Paracetamol, besides Roche machines for rapid anti-body tests, ventilators, testing kits and PPEs from abroad to ensure a reliable supply chain. As it happens, India itself has ramped up its own production of ventilators, APIs, PPEs etc. and is in a position to export its surplus.

Now that India is going to chair the WHO's Executive Board and politically sensitive issues such as the re-entry of Taiwan as an observer in the World Health Assembly and demand for an independent probe into the origin of the Wuhan virus in the interest of transparency and accountability – a demand that China opposes – will be on the agenda, Indian diplomacy will be tested. China continues to disregard India's core interests by not only aggressively claiming Indian territory while it seeks support from us for the so-called One-China policy, but also making repeated attempts to put the Kashmir issue on the UNSC agenda. It has just signed an agreement to build a large dam in India's territory in Gilgit-Baltistan. All this requires a riposte from India, one that is perfectly justifiable.

(The writer is a former Foreign Secretary. The views expressed are personal)

Decongesting cities for coping with Coronavirus

Prof. Ila Patnaik

The economic package announced by the Modi government has a strong rural bias that could help decongest cities. This is a pragmatic approach in the context of how the virus spreads. The virus is known to spread most among dense urban populations. Shared living spaces, where the poor sometimes reside, are most at risk. Nor can this strategy help increase rural incomes during the lockdown, it will address the uneven growth trajectory, with the agricultural sector lagging behind, that the Indian development model has witnessed. While the 1991 reforms liberalized India industry, it did not address agriculture and the sector continues to have laws and policies that have prevented its growth.

The next few months could be a difficult time for urban dense areas. The coronavirus could spread more easily in such spaces. This could result in urban clusters being declared hotspots and being locked down. As we move from a nationwide shutdown to a strategy of localized tight containment zones to contain the virus, the probability of a lockdown in urban working spaces is higher.

The economic package appears to be based on the belief that people will go back to their villages and try to find work there. For their survival production in rural India need to be boosted. Schemes for dairy, infrastructure, fishery, herbs, micro food units and farms have been

announced, in addition to freeing up farmers access to markets.

The government would spend Rs 3500 crore for foodgrain supply to migrants and Rs 1500 crore through interest subvention of 2% for Shishu loans under the Mudra Scheme. The government announced relief for street vendors, through a special credit facillity of Rs 5,000 crore.

However, a much bigger employment boosting measure in the government's stimulus package was an increased allocation of Rs 40000 crore to MNREGA. In another scheme the government would spend Rs 6,000 crore towards employment generation in forest areas.

In addition to changing personal and social behavior, the economy might change, if the virus is here to stay. Looking forward, if there is no universal access to a COVID-19 vaccine for another 18-24 months, then business in sectors and locations which are safer is likely to do well, while those at high risk may not be able to sustain operations. While liquidity is today one of the biggest obstacles to revival of business, we may find that even if credit is available, the possibility of another lockdown, of disrupted supply chains, of higher costs, and of unstable demand, may discourage many businesses from re-starting operations in dense urban clusters.

In contrast, the least risk of the spread of the virus and consequent lockdowns is in rural India where it is naturally easier to have physical distancing and outdoor work. This may shift the focus from urban markets to rural markets for both demand and production. Livestock, fisheries, dairy, vegetables, fruit and food processing are more labour intensive and high value yielding. After many decades of neglect in R&D, lack of market access, on-off policies for exports, and market distortions, the present adversity may be a timely opportunity for this sector. The

sector would need support of a suitable policy framework and reforms in pricing policy, tax, market access, credit and rural infrastructure like warehouses and cold storages. The next two years or so of how we learn to live with corona virus can redesign the economy towards safer and more sustainable production and consumption with agriculture and the rural economy as its strength, rather than its weakness.

From the economic package announced it seems that the government is trying to decongest cities. No big urban work fare program or an unemployed assistance program was launched. Not only would this not have been affordable, it might also not have been pragmatic if urban clusters were at high risk of becoming containment zones.

Right from the first GareebKalyan Program, or the first stimulus package, the focus has been assistance to rural areas, even though at that time migrant workers were being asked to stay where they were in cities. Now that provisions are being made for them to return to villages, the government needs to step up its efforts to give them incomes in rural areas through agricultural reforms.

Agricultural reforms

The agricultural reforms and schemes in the economic package seeks to give a push to agriculture to increase diversification towards higher value products. Through legislative reform the government seeks to do for agriculture what the 1991 reforms did for industry. Freeing up agricultural markets and greater access to markets for farmers lies at root of this strategy. The Finance Minister announced that the government will amend the Essential Commodities Act (ECA) of 1955, bring a Central legislation to allow farmers to sell their produce to anyone, outside

the APMC yards, create barrier free inter-state trade and enact a legal framework for contract farming. These will remove many restrictions on agriculture that have plagued Indian agriculture for many decades.

Some of the reforms, such as the promised laws on agriculture that the government has promised to enact such as an amendment to the Essential Commodities Act, a law that would allow contract farming and a centre that would remove barriers to interstate trade and commerce and create a national food market, would be game changers. Many governments have talked about these laws but no one has had the political courage to enact them. If the government is able to push through the legal changes then the liberalisation of agriculture would be akin to the 1991 liberalisation of Indian industry.

The measures announced for farmers in the economic package included Rs 2 lakh crore of concessional credit and Rs 30,000 crore working capital funding through NABARD. The FM announced the setting up of Rs 1 lakh crore agriculture infrastructure fund for financing projects relating to cold chains, storage infrastructure, strengthening of fisheries value chain through setting up of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana are expected to yield outcomes in the next few years. Rs 500 crore and Rs 4,000 crore were announced to be spent on supply chain disruptions and on promoting herbal cultivation. Other measures including for control of animal disease, development of animal husbandry infrastructure, micro food enterprises were also announced. Finally, for MGNREGA the allocation was increased by 40,000 crore.

If the next two to three years are genuinely devoted to increasing rural incomes by diversification, modernisation and liberalisation of Indian

agriculture, India could become a world leader in the production of fresh farm produce, herbs, organic fruit and vegetables.

By now it is understood that the fight against the novel coronavirus is not a short fight. Our understanding about the spread of the virus is evolving everyday with data and research. The alternative strategy of trying to sustain migrant workers in urban areas through transfer payments would not only have been unaffordable, it would have had adverse health implications.

(The author is an economist and a professor at the National Institute of Public Finance and Policy. Views are personal)

Aatma Nirbhar Bharat

Brig Anil Gupta

Towards the closing days of Lockdown 3.0 Prime Minister Modi gave the nation a clarion call of Aatm Nirbhar Bharat (Self-Reliant India). Amplifying his earlier statement of "Jaan Bhi Jahan Bhi", he asserted that "we have to protect ourselves and move ahead as well". He also announced a special economic package, and said the recent decisions by the government, the decisions by the RBI combined with the May 12 financial package announcement come to about ₹20-lakh-crore — nearly 10% of India's GDP. By recent government decisions he implied the immediate measures announced by the government for economic survival of the poor and weaker sections hit by the sudden announcement of Lockdown 1.0 in form of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana and a few other measures to fight the deadly pandemic which was the causa primaria of the Lockdown 1.0 which suddenly brought to halt the economic activity in the country and people were confined to their homes to maintain social distancing and stay safe.. The series of Lockdowns thereafter were termed by the PM as "Tyag" (sacrifice) and "Tapasya" (penance) of the people. The shift from initial "Jaan Hai to Jahan hai" to "Jaan bhi Jahan bhi" was realisation of the fact that Corona is going to stay and we have to learn to live with it.

PM said, "Corona crisis has also taught us the importance of local supply chains, local markets has stepped into help us. Time has taught us that we have to now think local. Even global brands were once local. When people used it, branded these products, marketed them, those products

became global from local. We need to be vocal for our local products. Not just buy but also publicise them." Quoting from Vedas, PM explained the importance of self-reliance,"Sarvam Aatmam Vasham Sukham. That which is in your control gives you happiness. We have to move ahead with new energy. We and we will make India self-reliant."

Modi also enunciated five pillars of Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan, "Five pillars will prop up this edifice, 1) Economy that doesn't talk of incremental change but a quantum jump. 2) Infrastructure. 3) Technologically driven systems. 4) Demography is our strength. Source of our energy. 5) Demand – we need to stoke demand and every spoke of our supply chain has to be strengthened. This supply chain will have the aroma of our country and the sweat of our labour." The PM also clarified that definition of self-reliance has changed post Covid-19, self-reliance does not mean "isolation" or "protectionism". India has always believed in "Vasudhaiva Kutumbakam" (world is one family). PM clarified, "Our definition of self-reliance is about including everyone, who believe the earth as mother. When such a country becomes self-reliant, then the prosperity and happiness of the world is included in it. The aims and works of India have an impact on the prosperity of the world."

Thereafter, the Finance Minister Nirmala Sitharaman in a series of five press conferences explained to the nation the fine details of the economic package which focused on land, labour, liquidity and laws, and catered to various sections including cottage industry, MSMEs, labourers, farmers, Self Help Groups (SHGs), middle class, industries, among others. The package is also meant to give requisite boost for the Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan through structural reforms, technology intervention and

improved measures for "ease of doing business." These included both fiscal and monetary measures.

Even before the FM had finished announcing all the tranches of the economic package a debate raged in the country terming the measures announced by the government as a "loan mela" rather than a 'stimulus package'. Those opposing the government advocated cash doles to the people engaged in different sectors so that the cash in hand would revive the demand cycle which as per them was a pre-requisite to revive production cycle. Those advocating the cash doles belonged to the school that believed in using the people as vote bank by pleasing them through appeasements and in the bargain always keep them dependent at their mercies rather than encouraging them to stand on their own feet and compete. The government did not concede to their pressure. The government insisted that there is a mix of fiscal impulses and liquidity provisions. In any case, the entire debate was ill-founded since the PM very clearly had announced an "economic package" and not merely a "stimulus package."

The opposition failed to grasp the concept of Aatm Nirbhar Bharat or deliberately chose to ignore it to gain sympathies of the people in order to nail the government and portray it as 'unsympathetic' and 'anti-people' to score brownies. But people of India hold PM Modi at a different pedestal and believe that he is not merely a politician but moral, social and sptritual leader of our vast country who has been ordained to make India "Sone ki Chidiya" again. That is why nation responds to him in a way it does to no other political leader. He has convinced the nation 'there is no gain without pain'.

It needs to be understood that the economic package announced by the

PM and slew of measures announced by the FM are not mere short term quick fix patch solutions but focussed time bound mission mode projects with necessary laws, liberalisation and financial support to enable farmers, companies and producers to compete at global level and ultimately lead the global supply chain in the new world order post Covid-19. The tendency to start counting eggs even before the chickens are hatched needs to be curbed and allow necessary time for the package to fructify and make real the dream of Aatm Nirbhar Bharat. Brand India, because of its quality, world class certification and competitiveness, will first dominate the local market and thereafter be envy of others in global market.

There are two components of self-reliant India. First is developing, promoting and selling world-class Brand India. The second one is to attract multi-national foreign companies desirous of re-locating from China post Covid by providing them business facilities and environment at least equal to if not better than China.

For making Brand India world class as well as affordable, we need to develop the talent and infrastructure for designing and producing products which compete with market leaders like I-phone, BMW, Samsung, Nike, Gucci, Honda, Google, Android etc without compromising on quality yet cheaper and affordable. Quality, reliability, visibility, affordability and ease of access are a few essentials for brand acceptability. As PM had said self-reliance does not mean using only swadeshi products but implies producing world-class quality products which would sell not only domestically but globally. Self-reliance does not mean that you depend on the free cash doles given by the government to sustain you but it means that you become a contributor to nation's economy by starting own business with incentives

and loans given by the government and stand gradually on your own feet. Once you are on your own feet, loan can be re-paid. Be a contributor rather than a dependant. In nutshell, there is a need to shed all our past inhibitions and forge ahead with a new mind-set. A positive mind-set of "We Can We Will." Future vistas in nuclear, space and geo-spatial space has provided wings for young start-ups to fly.

In order to be "vocal for local" aggressive brand promotion will be needed. Extensive use of television and social media platforms like You Tube, Facebook and others will enable instant brand visibility. It is the best opportunity for existing Indian companies like Reliance, Tata, Mahindra, TCS, Infosys etc to establish them as world class brands through aggressive advertising and turn this short term crisis into a long-term opportunity.

China's weakened global position is a God sent golden opportunity for India to attract more investment by providing environment for a new world factory. To begin with companies which already have some manufacturing in India may be interested to reduce stakes in China and scale up production in India. Bur that wouldn't suffice. The market is wide open and there are other competitors as well. In order to beat the other competitors we will have to not only provide supply chain infrastructure like large ports and highways, top quality and cheap labour and sophisticated logistics but continuity, stability and sincerity in our policies and regulations. A consistent and transparent FDI policy is also warranted. Bharat also needs to integrate with already existing regional supply chains through bilateral and multilateral agreements. Everything is achievable when there is sense of purpose, sincerity and submission to national interest. PM has already said "our resolve and determination are greater than the crisis."

The economic package announced by the PM and subsequent measures contained in five tranches are meant to enable us to do exactly what is needed to become vocal for local as well as draw international investment. It will provide our MSMEs a unique identity which they have been denied so far. It would formalise the Micro Food Enterprises by showcasing our diversity in which non –descript and remote towns have products which are unique as well as commercially viable. It would also enable us to "Think Global-Make Local." The scope is vast from wearables to organic wellness products, robotics, 3D printing, hospitality and clean energy products. We have to grow beyond pickles, pappad and handicrafts, not that they be ignored but our supply chain shouldn't be exclusive but include maximum possible products as per domestic and global need.

Make in India, Make for India, Make for World, the quintessential requirement of inclusivity is the key to provide global reach to the Vocal for Local programme-the spirit behind Aatm Nirbhar Bharat. PM's economic package is just an enabler. It provides for laying a foundation of taking a quantum leap. Those who dare to seize opportunity will come out winners!!!

(The author is a Jammu based veteran, political commentator, columnist, security and strategic analyst. The views expressed are entirely personal.)

PM Modi's Clarion Call for Atmanirbhar Bharat Abhiyan: A Game Changer for India's Resurgent Future

Pathikrit Payne

On May 12, 2020 Prime Minister Narendra Modi addressed the nation and announced an economic package of Rs 20 lakh crore along with declaring the broad blueprint of a new vision for a self-reliant India. Prime Minister Modi stated that his Government would essentially focus on not just buying more from the domestic companies but also appealed to the country at large to advocate and promote local products. He coined the term 'vocal for local' and envisioned the plan of his Government to create an 'Atmanirbhar Bharat' or a self-reliant India.

The Prime Minister's speech was followed by announcements of a slew of economic reforms by concerned ministries, in the following days, that charted the blueprint of unshackling several sectors from restrictive policies of the past, presented a new government policy of reserving government procurement up till Rs 200 crore for domestic companies only and heralding a new vision to unleash the potential of MSME sector and handholding them to become not just bigger through scalability but also globally competitive.

Some of the reforms including changes in the definition of MSME as well as proposal to amend the APMC act to allow farmers the freedom to sell their produce anywhere or anyone they prefer, by unshackling them from the clutches of the state controlled commission agents and powerful middlemen, are path breaking and boldest reforms that the country has witnessed since 1991.

Webbing an Opportunity for Nation in the Midst of a Crisis

Every crisis brings with it a new set of wisdoms and realisations for any society. In the midst of an unprecedented pandemic and uncertainty forced upon by the contagious COVID 19 virus, the nation needed a new idea to not just pass through the tumultuous phase and recover the economy, but also a spark to ignite and unleash the 'animal spirit' among the country's entrepreneurs, traders, industrialists and farmers. From here on India needs a structural metamorphosis for future resilience and no more just incremental changes to merely limp back to normalcy.

The magnitude of what the Prime Minister has stated, and the manner in which it would unleash a new India, would become evident to people only in the times to come. Many may not have comprehended yet the enormity of the vision that he has given a clarion call on. His mention of the need for 'Quantum Leap' instead of 'Incremental Leap' is exactly what India needs now.

PM Modi stated, "When the world is in crisis, we must pledge – a pledge which is bigger than the crisis itself. We must strive to make the 21st century India's century. And the path to do that is self-reliance"[i]. During his speech he also gave the example of how India transformed its PPE and N95 mask production capacity in the midst of the crisis.

"When the crisis began, not a single PPE was being manufactured in India. N-95 masks were being manufactured in negligible quantity. Today, the situation is such that India is manufacturing 2 lakh PPE kits and N95 masks each per day. We are able to do so because India has turned a crisis into an opportunity. India's vision to convert this crisis into an opportunity is going to prove influential as we become more self-reliant"[ii], the PM said.

Precedence from the Past: From Devastation to World Class

The Second World War (WW II) ended with unfathomable remnants of devastation all around. Not just Germany and Japan, even from the side of the victors, Great Britain, France and even Soviet Union were nothing better than a pile of debris with a major depletion of critical human resources, as a price of war, and with not much capital in hand to restore their respective broken nations. For Japan and Germany, the devastation was not just physical and economic, but deeply psychological too.

And yet, over the next four decades, both Japan and Germany had a phoenix like rise from ashes of debris to the pinnacle of technological prowess. Both Japan and Germany became synonymous with words like innovation and quality. German and Japanese brands became household names. The trust that Japanese brands like Sony, Hitachi, Suzuki, Mitshubishi or Toyota, to name a few, developed, could only be compared with German counterparts like Siemens, Volkswagen, Daimler, BMW, Bayer or Braun. Few would have thought in the aftermath of WWII that in a few decades' time, a customer from almost any corner of the world would take pride in ownership of any product made either in Japan or

Germany.

Why India Faltered in the Past but the likes of Japan and Germany Flourished…

Incidentally, it was barely two years after the end of WW II that India got independence from British rule. It was impoverished no doubt but it did not have a devastated infrastructure to deal with. India was not a country that was reduced to rubble by WW II. True, it had to start from basics of industrial development but it did have basic infrastructure at place. Yet, it could not, in the next four decades since 1947, reach anywhere near Japan or Germany in terms of industrial prowess.

On the contrary, Nehruvian protectionist policies resulted in restricting the elbow room of Indian industry and suffocated them with an obstructive industrial licensing policy coupled with inspector raj. The socialist penchant for reserving innumerable products for exclusive manufacturing by small scale industry and a general disdain for capital, resulted in Indian industry perpetually failing to leverage the power of scalability, or economy of large scale production, thereby eventually losing out in the global markets both in terms of qualitative and quantitative production.

Agricultural legislations such as APMC Act perpetually did away with both the bargaining and purchasing power of the Indian farmer thereby keeping him impoverished and perennially at mercy of the state and middlemen. As a result domestic demand never reached its optimum potential for long. India thus merely limped along with a perpetual foreign exchange reserve crisis and a faltering economy that did not encourage innovation or aspiration.

Sadly, Since Independence the Indian approach was always Incremental and not Quantum

Perhaps the reason why India could never catch up with Japan and Germany was because they were thinking of quantum leap since 1945 while India's policy makers were thinking of incremental change since 1947. Even during India's economic liberalisation initiated in 1991 out of an unprecedented balance of payment crisis, the reforms were incremental and not structurally quantum in nature.

Prime Minister Modi is perhaps the first Indian Prime Minister who has openly talked about unleashing India's powers through quantum leap, structural reforms and by doing away with all the restrictive practices that prevented access of Indian private sector in many sectors. In fact, GST and Insolvency & Bankruptcy Code Act are some of the major structural reforms that have already been implemented by PM Modi that previous regimes dithered to implement.

For the first time an Indian Prime Minister has asked Indians to take a pledge to make 21st Century as India's century, and no more perceive India as a third world economy simply playing the catch-up game. For the first time an Indian Prime Minister has shown the resolve to pledge support for Indian industry get into the global league and become part of the global supply chain. Since independence, Industry in India has always been looked as pariah by every politician for fear of losing socialist tag even though it is always the industrial infrastructure of a nation that plays a key role in alleviating national poverty.

Charting a New Path for Small & Medium Industry: Aspire to Get Bigger

Prime Minister Modi during his speech specifically mentioned about the need to take care of every stakeholder in the supply chain. This is an important statement from the perspective of making sure that the ancillary industries and component manufacturers, most of which fall in the MSME (Micro, Medium and Small Enterprises) category, are adequately nurtured for their leap into the next league.

By bringing a fundamental change in the definition of MSME, thereby giving them the elbow room to grow, Modi Government is unleashing the power of 63.4 million units[iii] which contribute nearly 30% of India's GDP but is yet to realise its full potential.

Essentially what this is going to do is to make sure that many of India's 'unicorns' in the MSME sector would start aspiring to grow bigger instead of preferring to stay small. Their individual growth stories and collective aspirations to become part of the global supply chain would not only take India to a different league of industrial evolution but also would create a large array of jobs in the country that is essentially needed to cater to the need for rising population of labour force.

Every Global Giant was once a Small Entity and then it became a Behemoth

For long, in the name of protecting small industries, India had extremely restrictive policies for the small scale sector. No one was allowed to become bigger.

No one wanted to become bigger for fear of losing the incentives of the small scale sector. This resulted in impeding the aspirations of SSI (Small Scale Industry) sector and their hunger for growth. Consequently, in many cases, India's MSME sector found it difficult to compete with

their Chinese counterparts because India's SSI sector did not have the advantage of leveraging scalability to reduce cost by producing in large quantity, since India's restrictive policies prevented that. What Modi Government is aspiring to do is to make sure that India's SSI sector is given the wings to fly and attain global scale.

It has to be remembered that every major global brand, be it Japanese, German, American or Korean or from anywhere else, was once a small local player, like India's MSME players, and then they aspired to become regional or national in their footprints thereby eventually taking the final leap towards the global journey of fame, respect and acceptance. In many cases, the national governments have consistently helped their domestic companies emerge global through different means. It is a norm than an exception in case of China and Russia or even US where domestic companies are provided with cheap finances and governmental backing to gain global foothold.

For the first time, an Indian Government, under Prime Minister Modi, has shown the same resolve because in today's era, the clout of a nation is not just about military power but economic clout as well that results out of the strength of its industry. The United States for example, is consistently charting a protective architecture and attempting to negotiate favourable trade deals to support its domestic manufacturing and create jobs within the country. Global defense industry consists of major private players often backed in the global market by their respective governments.

The Legacy since 1947: Fantasy for Imported Goods & Decay of Indian Innovation

One of the most important aspects of the Japanese or German or even

the French or Korean growth stories is that people of these countries always took pride in buying the products of their own countries. One would never find a Japanese feeling superior by buying an American or a German product. The same goes for the German or the Korean. However in India, a different culture was created and embedded in the Indian psyche, which had its genesis in the British rule but was carried forward even after independence.

The British Empire, having destroyed indigenous industries of India, swamped the country with imported goods brought from Britain. Those who could afford those products felt a sense of belonging to a higher echelon of the society by virtue of ownership of those products. Post-independence, a combination of myopic protective policies and a general disdain and suspicion towards private enterprises, restricting access of, and competition from private sector in many domains reserved for state controlled enterprises, made sure that India's products during the Nehru-Indira socialist era were never world class because the state never encouraged development of world class products through competitive innovation. This legacy continued in some sectors even after economic liberalisation that started in 1991. State-owned enterprises, assured of market and immune from competition, never had a reason to strive for excellence. As a result, India suffered and for long had to remain dependent on imports of critical products and technologies.

Thus, while the ruling elites would import the best of the things from abroad, the mass were made to do good with whatever mediocre products that were made in India even as most nurtured a desire to someday own a foreign product. Even owning something as rudimentary as an imported

soap or perfume was a matter of pride and a 'dream come true' for the teeming millions during the socialist era of India.

Journey from 1991: Commendable but India Inc. Yet to Leverage its True Potential

Post economic liberalisation of 1991, in the unshackled environment, Indian industry did make major strides and in the last three decades took India from the shores of balance of payment crisis to a $3 trillion economy with around $480 billion in foreign exchange reserves. In 2018, seven Indian companies were in the Fortune Global 500 list. Several Indian companies also feature regularly in many other global ranking of companies. From automobile to generic drug manufacturing to IT services industry, Indian companies have made themselves reasonably well known in global arena. Over the last two decades hundreds of foreign companies, big, medium and small, have been acquired by their Indian counterparts to expand India's footprint in the global business matrix.

Yet India is yet to unleash its real potential.

PM Modi's clarion call to people of India to not just embrace local products but to also become vocal, or rather become brand ambassadors of them, is perhaps the first concerted effort by any statesman of India to push Indian companies for a greater pie in the global business matrix.

Decision of Modi Government to open all sectors to private players and reserve participation in tenders worth up to Rs 200 crore for Indian companies only, has to be immensely appreciated. Access of Indian private sector to sectors hitherto restricted to state owned companies would help in developing healthy competition and encourage innovation for quality products to reduce imports.

World Class Swadeshi Products for the Global Market

Prime Minister Modi's pitch for Atmanirbhar Bharat and 'Vocal for Local' slogan is much more than the generic Swadeshi movement which, even though was noble in essence, was more isolationist in nature. Instead,

PM Modi's clarion call is for not just making Indian products more popular in India but to eventually make sure that Indian brands become synonymous with quality and become household names globally. PM Modi is talking about integration and not isolation from global economy. In other words, globalisation cannot be just about FDI coming to India but also about Indian companies becoming global and investing in resources and markets elsewhere to expand the Indian footprint.

This though is happening for many years now but it needs to be institutionalised with active help of Indian Government.

For long, Japan or Germany or USA's global prowess has been based upon their hold on the global economy, something which China has emulated in the recent past. If India has to take the quantum leap from the present $3 trillion economy to $38 trillion by 2050 as per the Goldman Sachs' prediction, then Indian companies making it big in the global arena has to become a norm than an exception. This though has to be complemented with also making India a major hub for global manufacturing through the 'Make in India' initiative. Several global companies have evinced interest in shifting their global manufacturing bases to India in the recent past. It is also important here to mention that Indian industry too needs to spend much more on R&D, and make innovation a norm, to make their mark a permanent one in global arena.

The Supply Chain & Future Market Factor

A critical lesson for India during the COVID19 crisis is the importance of developing a comprehensive domestic supply chain to make sure that during global disruptions such as the on-going pandemic, India's production of critical commodities is not hampered. There lies the need of giving due importance to the component manufacturers and every stake holder of the supply chain that PM Modi emphasised upon. Making sure that India develops proficiency in the component manufacturing would immune India from supply chain disruptions of future. It has to be remembered that making components in India are as important as assembling the final products in India.

Also, the post-COVID19 global market matrix would be challenging. A major slowdown is gripping the whole world paralysed by the pandemic related lockdowns everywhere. Global demand for goods and services is reaching a new nadir. The shocking drop in price of oil and the resultant impact on the oil exporting economies shows the vulnerability of dependence on export alone to drive an economy.

Future Progress would depend on Deepening the Internal Economy

Expanding the horizon of the domestic economy would make sure that resilience of India's domestic economy would shield the nation during the times of global disruptions. Related to this are the bold steps of farm related reforms including proposed amendment to APMC Acts that would unshackle the farmers and give them the freedom to sell their produce to anyone of their preference. This is expected to have a major positive impact in terms of increased bargaining power of the farmer and rise in his disposable income which in turn is expected to have a major multiplier effect in terms of upsurge in demand for goods and services in

rural and suburban India, thereby helping strengthening of the domestic economy further.

A New Era of Resilient and Resurgence has Just Begun for India

India has survived the most difficult part of the COVID19 pandemic and has performed much better than many of the much famed western countries. The country with such an enormous population, nearly four times of that of US, showed reasonable discipline during the lockdown phases. In spite of various challenges, and political rabble-rousers, vested interests of various shades attempting to vitiate the environment, people, by and large, have abided by the appeal of PM Modi during lockdown.

The Indian industry has shown tremendous resilience in terms of not just surviving, in spite of massive challenges, but also metamorphosing to start production of critical commodities including PPE, ventilators and essential drugs. People have helped each other and the country never needed any external help to withstand the crisis. India did everything on her own and extended helping hand to others as well.

If PM Modi's vision for Atmanirbhar Bharat is properly implemented, along with development of resilient infrastructure and further easing of doing business, India would emerge as not just an immensely resilient country but would reach the pinnacle of global contribution based on the hard work, innovation and enterprising endeavours of a billion plus people. The journey then towards a $5 trillion economy by 2025, a $10 trillion economy by 2032 and $38 trillion[iv] economy by 2050 (as envisioned by Goldman Sachs) would be seamless and people would only realise then the essence of what the Prime Minister of India stated in his vision for Atmanirbhar Bharat on 12th May 2020.

References:

i. Refer to https://www.news18.com/news/india/modi-says-india-turned-virus-crisis-into-opportunity-cites-example-of-ppe-kit-n95-mask-production-2617265.html

ii. Refer to https://www.indiatoday.in/india/story/pm-modi-lockdown-speech-self-dependency-economic-easures-1677266-2020-05-12

iii. Refer to CII page on MSME (https://www.cii.in/Sectorsaspx-?enc=prvePUj2bdMtgTmvPwvisYH+5EnGjyGXO9hLECvTuNuX-K6QP3tp4gPGuPr/xpT2f

iv. [iv] Refer to Page 149 of BRICS & Beyond, https://www.gold-mansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/brics-book/brics-full-book.pdf

(The writer is a New Delhi based Policy Analyst. The Views expressed are personal.)

UP, not Kerala deserves to be lauded as the Model Covid Control State of India

Debjani Bhattacharyya

Apart from elucidating why UP, & not Kerala, deserves to be lauded as the Model Covid Control State of India, this article also aims at depicting what West Bengal is doing vis-à-vis UP to contain Covid. Comparison of UP with West Bengal is necessary to let people know that if UP may be considered as the positive reference standard for India, West Bengal may be taken as the negative reference frame thereof.

As Indian Mainstream Media is lauding Kerala Model of Covid Control & remaining silent about UP, it is necessary to let people know how the largest State of India, UP, with largest population is doing a silent revolution in Covid Control. People of West Bengal, having experienced Left Rule since 1977 & Ultra-left Feudal rule since 2011, are well-aware of LEFT LEGACY of manipulation & misrepresentation of data & information. People of WB are also aware how well orchestrated the Left propaganda machinery is. Hence, whatever the media may say about Kerala Model, the credibility would remain low, at least to a significantly large section of the people of Bengal. Even if Kerala is truly doing an excellent job with respect to Covid, doubts would remain as it's a matter of low credibility of the Lefts which has resulted from the political discourse over the years.

Statistically too, the State of Kerala cannot be marked as the representative State of India, which UP can be. Estimated population of UP in 2020 is 23.15 crores while that of Kerala is only 3.47 crores. Uttarpradesh can rightly be said Mini India as the State represents India in terms of demographic variety & homes 16.77% of total Indian population. Apart from demography, UP is a representative State of India with regard to its geographical span, diversity of culture, food habit & public-psyche too, while Kerala is not so. Moreover, average level of Education in Kerala is higher than the National average while that in UP is lower. With all characteristic deficits, UP's achievement in Covid Control has surpassed the achievement of Kerala & perhaps all other States. Hence, instead of focusing on Kerala Model, it would be more accurate to focus on UP Model of Covid Control for drawing a reference for whole India.

As on June 2, 10.20 pm:

UP

Confirmed Cases: 8361

Recovered Cases: 5030

Death: 222

Active Cases: 3109

Death as % of Closed Cases: 4.23%

Kerala

Confirmed Cases: 1413

Recovered Cases: 627

Death: 12

Active Cases: 774

Death as % of Closed Cases: 1.88%

West Bengal

Confirmed Cases: 6168

Recovered Cases: 2410

Death: 335

Active Cases: 3423

Death as % of Closed Cases: 12.20%

As par official data, Kerala has done really well in Covid Control. However, data of a Left ruled State is not beyond doubt.

UP CM Yogi Adityanath came on RITAM LIVE on May 24 & was asked about the procedure UP had followed to contain the disease. UP CM described it sitting on his chair at a stretch for an hour without looking at any paper or having anyone sitting beside him to prompt with any data. This gesture of UP CM is in strict contrast with WB CM's who sits on Press Meets with her full him of Bureaucrats, Doctors & other aides around. Her aides prompt her with data, info & even correct linguistic expressions.

UP CM's PRESS LIVE showed that CM himself was perhaps integrally involved in each part of the State's administration while WB CM remains more engaged in power politics. While Mamata Banerjee is predominantly a politician, Yogi Adityanath appeared to be a man of Administration. The clarity & detail of his presentation resembled those of an administrator more, than of a politician.

UP took Covid challenge as an opportunity, said the CM, giving sole credit to PM Modi's vision & guidance. In order to check Covid spread within UP, the State formed different Committees under the leadership of different Ministers & Bureaucrats. Ministers took policy decisions while Bureaucrats decided implementation modalities thereof, said Yogi

Adityanath. To ensure Governmental Services reach every section of the population, several Governmental Committees were formed under the leadership of senior bureaucrats.

- One committee looked after comprehensive requirements & issues related to construction workers of the State whose work got stopped due to lockdown.
- One committee mapped necessities of the State's thela-walas, patri-walas& such other service-providers.
- One to look after requirements of self-employed professionals like rajmistris, carpenters, saloons, tailors, etc who provided essential services in both rural & urban lives.
- A committee under the Directorate of Infrastructure & Industrial Development looked after necessities of the State's Enterpreneurs, Industrialists as well as the workers thereof.
- This Committee worked so that people working under different enterprises & industries got their salaries during essential lockdown & also got catered with ration & requirements.

UP thus divided the whole State Population into professional categories for administrative ease. Yogi's administration addressed the fact that people's requirements depend on their professional identities & public welfare can be done best by identifying their needs & necessities. This work appears primary, not only for Covid control but for any policy decision of a State. No wonder UP CM said the State looked at Covid challenge as an opportunity. UP worked heart n soul to turn the challenge into a success that sustains in post-Covid era. UP's novel administrative reforms are expected to yield manifold in due course of time.

- One committee under Agriculture Department ensured home delivery of essential commodities to every door step. This step taken by UP Govt was a pre-requisite to make lockdown a success. This Committee extended its sub-committees at every level of the State like District, Block, Ward& Village. In a huge State like UP, this single work perhaps did half of Covid Control. Without ensuring availability of necessary stuff to people's doorsteps, lockdown was indeed a draconian step. But UP Govt. did their part by providing home delivery.

On the contrary, we have seen mockery of lockdown in West Bengal as people huddled in open market everyday with apparent support of WB Government. Lockdown remained half-hearted in West Bengal all through as certain minority dominated areas didn't abide by lockdown rules at all. Minority people kicked Howrah City Police in Tikiapara as Police tried to enforce lockdown rules upon them. When IMCT arrived in Kolkata, West Bengal CM had to pray with folded hands in Rajabajar so that people of minority community there followed lockdown rules. Did she have to do it to save her own face as an administrator in front of the inter-ministerial central team?

While such chaotic is the administrative scenario of West Bengal, UP CM, in reply to my specific question, said that nobody in UP ever violated lockdown rules as UP administration handled it right. This distinct contrast exists between administrative approaches of WB & UP.

As of 2nd June, only 4.29% of closed COVID cases of UP had died whereas in West Bengal, death percentage of closed COVID cases is 12.20%, almost 3 times higher than that in UP. This perhaps indicates quality of Covid treatment provided in WB is worse than that in UP. Morever,

this figure is as per Official Data of West Bengal which has consistently exhibited statistical anomalies in several parameters. Unofficially, number of Covid affected patients & number of death thereby in WB are perhaps much higher than what is being reported. As mentioned earlier, data manipulation & misrepresentation have been hallmark of Left & Ultra-left ruled West Bengal for decades. There are no such anomalies in UP.

- In UP Covid Model, one Committee worked under Principal Secretary, Rural Development & Panchayati Raj to facilitate effective prevention of various vector-borne disorders like Dengue, Malaria, Kala-azar etc. well in advance. These diseases affect UP every year during rainy season. UP Govt, along with fighting COVID, became pro-active to prevent these diseases by emphasizing on SWACHHTA (cleanliness) & sanitation of susceptible places from now on. The State utilized the opportunity of tackling Covid to tackle other diseases too.

We have never seen this pro-activity in West Bengal. West Bengal is the only State of India which is hiding its Dengue data from GOI for last two years. National Vector Borne Disease Control Program's (NVBDCP) site did not record WB's Dengue data from 2018. WB gets tremendously affected by Dengue every year. The reason thereof is perhaps lack of cleanliness with respect to the State's huge population density. Instead of sanitizing & cleaning Dengue-prone areas, WB Govt hides cases by instructing doctors not to certify the disease as 'Dengue' but as 'Acute Febrile Disorder'. UP, on the other hand, took Covid Control Program as a scope to be pro-active to prevent vector-borne diseases too which would affect UP shortly after summer, during rainy season. West Bengal however, preferred to hide its COVID data just as it had hidden its Dengue

data since 2018.

This paradigm shift is making a world of difference between UP & WB. UP is in fast progress while Bengal eroding steadily. Moreover, after UP has worked with this detail & achieved significant success in Covid Control, it is UP & not Kerala that deserves to be the Reference Model of Covid Control in India.

(The Author is an Communication Strategist, Business Consultant & Columnist. Views expressed are personal.)

चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास है आत्मनिर्भर भारत अभियान

हर्षवर्धन त्रिपाठी

विश्व के दूसरे देशों की तरह भारत भी चाइनीज वायरस प्रकोप से जूझ रहा है। हालांकि, समय से हुई देशबंदी और उस समय का प्रयोग इस बीमारी से लड़ने के लिए के लिए तैयारी करने से भारत की स्थिति दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर रही है, लेकिन देशबंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट पहुंची है और इसीलिए देशबंदी को शर्तों के साथ खोलते हुए भारत सरकार ने देश के अलग-अलग वर्गों को राहत देने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज का एलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक पैकेज का एलान करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि यह पैकेज सिर्फ कोरोना वायरस से उपजी स्थितियों को ठीक करने भर के लिए नहीं है बल्कि यह पैकेज नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तय किए आत्मनिर्भर भारत को तेजी से प्राप्त करने का संकल्प भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैकेज का एलान करते हुए कहा था कि पहले के एलान और राहत को मिलाकर कुल 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का पैकेज सरकार दे रही है। जाहिर है इसमें लोगों को सीधे तौर पर रकम देना, जरूरतमंदों को राशन देना, अस्थाई रोजगार के मौके उपलब्ध कराना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देना, कृषि क्षेत्र और उद्योगों को जरूरत भर की रकम आसान शर्तों पर उपलब्ध कराना शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान विशेष आर्थिक पैकेज के पहले ही देशबंदी के साथ 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज से लोगों को राशन और जरूरतमंद के हाथ में रकम दी थी। इसमें किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग शामिल थे। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज की किश्तें 3 महीने बाद देने की सहूलियत के साथ ही कर्ज पर ब्याज की दरें भी कम की थीं। हालांकि, बैंकों ने रिजर्व बैंक की दी सहूलियत को पूरी तरह से ग्राहकों को नहीं दिया। साथ ही रिजर्व बैंक ने डूबे कर्जों के मामले में भी बैंकों और कर्ज लेने वालों को राहत दे दी है और इन सबके साथ एकदम से ठप पड़ गई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन चाइनीज वायरस की मजबूरी में बंद हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी दे दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत विशेष अभियान आर्थिक पैकेज का एलान करते हुए 4 महत्वपूर्ण सुधारों की बात की थी। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। लिक्विडिटी यानी लोगों के हाथ में और बाजार में नकदी को लेकर रिजर्व बैंक लगातार फैसले ले रहा था और अब जमीन और श्रम से जुड़े बड़े सुधारों का इंतजार सभी को था। साथ ही कानूनी दिक्कतों को दूर करके कारोबार और कृषि से जुड़े कारोबार को बेहतर करने की भी एक आस बंधी थी। अलग-अलग चरणों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक-एक करके जमीन, श्रम, नकदी और कानून से संबंधित ऐतिहासिक सुधारों का एलान आत्मनिर्भर भारत अभियान विशेष आर्थिक पैकेज के जरिये किया। इसकी आलोचना भी इसी वजह से हो रही है कि यह ऐलान फौरी राहत से ज्यादा लंबी अवधि की योजनाओं को बताने जैसा दिख रहा है। काफी हद तक यह आलोचना सही भी है कि करीब 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का बड़ा हिस्सा फौरी राहत पर केंद्रित नहीं है बल्कि दीर्घकालिक अवधि में भारत के आत्मनिर्भर होने की योजना को लागू करने के लिए किए गए एलान हैं। 5 चरणों में वित्त मंत्री के एलान में कुल 9 लाख करोड़ रुपये के एलान ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक के कदम हैं और इसके अलावा पहले चरण में 1 लाख 92 हजार करोड़ रुपये, दूसरे चरण में 5 लाख 92 हजार करोड़ रुपये, तीसरे चरण में 3 लाख 10 हजार करोड़ रुपये और चौथे चरण में 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं, राहत का एलान किया गया। पांचवें चरण में करीब 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सबसे बड़ी जरूरत अभी इसी बात की है कि किसी भी तरह बंद पड़े उद्योगों को शुरू किया जाए। सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्योगों का संकट बहुत बड़ा हो गया है। करीब 2 महीने की पूर्ण बंदी के बाद उनके पास नकदी का गम्भीर संकट है और कई उद्योगों को डूबने का खतरा खड़ा हो गया है। इसके लिए जरूरी था कि तुरन्त उन्हें आसानी से और बिना किसी गारंटी वाला कर्ज मिल सके, जिससे उद्योग अपना काम शुरू कर सकें। इसलिए देश की करीब 45 लाख एमएसएमई कंपनियों को इसका लाभ देने के लिए कारोबारियों, खासकर एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमर्जेंसी वर्किंग कैपिटल फेसिलिटी दी गई। इस 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी पूरी तरह से केंद्र सरकार की होगी, इससे बैंकों या एनबीएफसी के कर्ज डूबने का खतरा नहीं होगा, इससे बैंक कर्ज बांटने में आनाकानी कम करेंगे। 4 वर्ष के लिए यह कर्ज दिया जाएगा और उद्योग 12 महीने के लिए मूल धन का भुगतान टाल सकते हैं। ऐसे छोटे और मंझोले उद्योग जिनका कर्ज एनपीए हो रहा है, उनके लिए विशेष तौर पर 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज दिया गया है। देश के करीब 2 लाख छोटे, मंझोले उद्योग हैं, जो कर्ज नहीं भर पाए और एनपीए हो गया या मुश्किल में हैं। बैंक ऐसे सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्योगों को उनकी कंपनी की हैसियत का 15 प्रतिशत तक जो अधिकतम 75 लाख रुपये होगा, कर्ज देंगे।

10 हजार करोड़ रुपये का शुरुआती फंड एमएसएमई के फंड ऑफ फंड्स के लिए, नए उद्यमियों के काम आएगा। ऐसी कंपनियां जो बाजार में सूचीबद्ध होना चाहती है उनके लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। 10 हजार करोड़ रुपये का शुरुआती फंड है और इसमें इक्विटी के जरिये फंड जुटाया जाएगा। एक बेहद जरूरी सुधार था कि एमएसएमई की परिभाषा बदली जाए जिससे एक तय आकार से ज्यादा बढ़ने के बावजूद कंपनी को लाभ मिल सके। अब एमएसएमई की परिभाषा बदल दी गई है। अब कंपनियों के निवेश और टर्नओवर, दोनों ही आधार पर एमएसएमई की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। बदली परिभाषा में माइक्रो, सूक्ष्म उद्योग निवेश 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक, स्मॉल – निवेश 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़, मीडियम, मध्यम 20 करोड़ निवेश, टर्नओवर 100 करोड़। 100 करोड़ तक वाली कंपनियां एमएसएमई के दायरे में आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों क्षेत्रों की एमएसएमई को अब बराबर लाभ मिल सकेगा। ट्रेड फेयर और एक्जिबिशन नहीं हो रहे हैं, इसलिए ई मार्केट लिंकेज को प्रोत्साहित किया जाएगा। 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, इसको ऐसे समझिए कि छोटे, मंझोले उद्योगों को 200 करोड़ तक के टेंडर में विदेशी कंपनियों से मुकाबला नहीं करना होगा, छोटी कंपनियों को सरकारी काम मिल सकेंगे। सरकार या सरकारी कंपनियों में लंबित भुगतान 45 दिन के भीतर दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने पहले ही 3 महीने के लिए कंपनियों के उन कर्मचारियों के लिए ईपीएफ का हिस्सा दिया था, जिनकी तनख्वाह 15000 रुपये तक है, अब जून, जुलाई और अगस्त के लिए सरकार ईपीएफ की रकम भरेगी, केंद्र सरकार 2500 करोड़ रुपये देगी और 72 लाख कर्मचारियों को फायदा जून, जुलाई और अगस्त के लिए ईपीएफ की कंपनी और कर्मचारी की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई, इससे कर्मचारी और कंपनी दोनों के पास ज्यादा रकम हाथ में आएगी, कंपनियों के पास 6750 करोड़ रुपये आएंगे। NBFC, HFC, MFIs के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटी योजना, इससे NBFC, HFC, MFIs को 30 हजार करोड़ रुपये मिल सकेंगे, इससे हाउसिंग सेक्टर को भी लाभ मिलेगा। NBFC और MFIs को 45 हजार करोड़ रुपये की आंशिक कर्ज गारंटी, इसमें कर्ज न चुका पाने वाली कंपनियों का पहला 20 प्रतिशत सरकार देगी।

राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया था। डिस्कॉम, बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये की मदद दी गई है। बिजली वितरण कंपनियों को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन के जरिये कर्ज दिया जाएगा, इसमें गारंटी राज्य सरकार की होगी, इससे बिजली वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन कंपनियों का कर्ज चुका सकेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी

से कंपनियों, ठेकेदारों के डिफॉल्ट होने का खतरा साफ दिख रहा था। इससे कपनियों को बचाने के लिए ऐसी सभी परियोजनाओं को, जिन्हें अभी पूरा होना था और नहीं हो पाईं, उनके लिए 6 महीने का विस्तार दे दिया गया है। साथ ही सरकारी एजेंसियां आंशिक तौर पर गारंटी भी देंगी। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए 25 मार्च 2020 तक पूरी होने वाली हाउसिंग परियोजनाएं को 6 महीने का विस्तार दिया गया है।

जिन लोगों को भुगतान टीडीएस काटकर मिलता है, उनके हाथ में ज्यादा रकम पहले ही रहेगी, हालांकि इसमें एक जरूरी बात समझने की है कि अगर टैक्स लिमिट के लिहाज से उनकी देनदारी नहीं बनती है तो टैक्स रिटर्न के बाद रिफंड में रकम पहले भी वापस आ जाती थी, अब पहले ही 100 रुपये की जगह 75 रुपये ही कटेंगे, निजी तौर पर भले लोगों को बहुत फर्क न पड़े, लेकिन कुल मिलाकर 50 हजार करोड़ रुपये लोगों के हाथ में आएंगे। सरकार ने 45 दिन के भीतर सभी तरह का बकाया भुगतान तुरन्त करने का एलान भी किया। केंद्र सरकार के एलान के साथ ही सरकारी विभाग तेजी से कार्य करने में भी जुट गये हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि उनके मंत्रालय से संबंधित 90 प्रतिशत कार्य शुरू हो चुके हैं। करीब 170 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग की इन परियोजनाओं में लगे मजदूरों को रोजगार मिल गया है।

अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़े, यह सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है कि हर हाल में प्रवासी मजदूर को जरूरी राशन, नकदी मिल सके। एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये के शुरुआती ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का जोर इसी बात पर था। 3 महीने के लिए राशन उपलब्ध कराया गया था अब अगले 2 महीने- मई और जून- के लिए सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हर प्रवासी परिवार को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना, बिना राशन कार्ड के भी यह लाभ मजदूरों को दिया गया है। 8 लाख टन अनाज और 50000 चना इसके लिए आवंटित किया गया है। प्रवासियों को एक राशन कार्ड के दूसरे राज्य में प्रभावी न रह जाने से भी बड़ा संकट खड़ा हो रहा था। राशनकार्ड धारक होने के बावजूद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लाभ नहीं मिल रहा था। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अब 23 राज्यों में लागू हो चुकी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले कुल 67 करोड़ लाभार्थी अब दूसरे राज्यों में राशन ले सकेंगे। कुल राशन कार्ड धारकों का 83 प्रतिशत है। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति ने करीब एक दशक पहले यही सुझाया था कि तकनीक के प्रयोग से अनाज का वितरण हो, जिससे उपयुक्त लोगों को आसानी से समय से राशन मिल सके।

एक बहुत बड़ी योजना का एलान इस पैकेज में किया गया है, अगर हर शहर में अगर स्थाई रूप से ऐसी

रिहायशी योजना लागू की जा सके तो औद्योगिक शहरों में झुग्गियों के बनने से पहले ही उस पर रोक लगाई जा सकती है। शहरों की बुनियादी सुविधा और श्रमिकों के जीवनस्तर की बेहतरी के लिए यह योजना चमत्कारिक प्रभाव वाली हो सकती है। श्रमिकों को सस्ते घर किराए पर मिल सकें, इसके लिए एक बड़ी योजना का एलान आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में किया गया है। इस योजना में सरकारी आवासों को निर्माण इकाइयों, उद्योगों, संस्थाओं के साथ मिलकर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बदला जाएगा। पहले से दिए जा रहे मुद्रा कर्ज में शिशु मुद्रा कर्ज में एक वर्ष तक के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज छूट का एलान इस पैकेज में हुआ है। 50 हजार रुपये तक के कर्ज को शिशु मुद्रा कर्ज का दर्जा है। अभी तक 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये का शिशु मुद्रा कर्ज दिया गया है। इससे शिशु मुद्रा कर्ज लेने वालों को 1500 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

एक बहुत जरूरी घोषणा स्ट्रीट वेंडर- रेहड़ी, पटरी वालों के लिए की गई है। सड़क किनारे अपना छोटा काम करने वालों की मदद के लिए 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ऐसे सभी रेहड़ी, पटरी, खोमचे वाले को 10 हजार रुपये की मदद दी जाएगी, इससे देश भर में करीब 50 लाख लोगों को मदद मिल सकेगी, जिनका काम धंधा इस दौरान पूरी तरह से ठप पड़ गया। मध्य आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज देने का एलान किया गया है। इससे 6 से 18 लाख रुपये सालाना आमदनी वालों को सस्ता कर्ज मिल सकेगा। इससे हाउसिंग क्षेत्र में मांग बढ़ेगी और स्टील, सीमेंट और दूसरे निर्माण सामग्री वाले क्षेत्रों की मांग बेहतर होगी। वनाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिए शहरी और वन क्षेत्र को 6 हजार करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। 30 हजार करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त आपात फंड किसानों को ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिये नाबार्ड के जरिये उपलब्ध कराया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 2.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन किसानों के लिए असली राहत न तो कर्ज का मिलना है और न ही हाथ में कुछ नकदी का मिलना।

किसानों के लिए असली राहत है कि उसकी उपज की बेहतर कीमत उसे मिल सके और इसके लिए सबसे जरूरी था कि किसान को अपनी उपज की कीमत तय करने का अधिकार मिले, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कृषि प्रधान देश भारत में किसान को उसकी उपज की कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिल सका। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान सही मायने में कृषि क्षेत्र के लिए हुए ऐतिहासिक सुधारों से होने जा रहा है। भारतीय कृषि के लिए इससे बड़े सुधार कभी नहीं हुए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बड़ा

बदलाव किया गया है और उपज क खरीद-बिक्री को एपीएमसी मंडियों के दायरे से बाहर लाया गया है। अब किसी भी उपज पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं लागू होगी। इससे कृषि भंडारण और उससे जुड़े क्षेत्रों में बड़े निवेश का द्वार खुल रहा है। कृषि क्षेत्र की बुनियादी सुविधा पर 1 लाख करोड़ रुपये का खर्च सरकार करने जा रही है। इससे किसान उत्पादक संगठन, कृषि सहकारी समितियां, भंडारण और दूसरी खेती से जुड़ी सुविधाएं मजबूत होंगी। पैकेज के एलान के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से 74 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की उपज खरीदी जा चुकी है और पीएम किसान के तहत किसानों के खाते में सीधे करीब 19हजार करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। दुग्ध क्षेत्र पर 15 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट फंड के जरिये दुग्ध क्षेत्र में बेहतरी की संभावनाएं तलाशकर उन पर काम होगा। माइक्रो फूड एंटरप्राइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

एक अतिमहत्वाकांक्षी एलान है हर्बल उत्पादन के लिए गंगा के पाट का प्रयोग। इसके लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर जमीन पर हर्बल उत्पाद की संभावनाएं तलाशेगा। वोकल फॉर लोकल और देसी उत्पादों की ब्रांडिंग पर विशेष जोर होगा। कश्मीर का केसर, आंध्र प्रदेश की मिर्च, कर्नाटक की रागी, हल्दी और बिहार का मखाना जैसे विशुद्ध भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर जोर देने की बात भी आर्थिक पैकेज के जरिये की गई है। टॉप टू टोटल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसमें ज्यादा उत्पादन वाले क्षेत्र से कम उत्पादन वाले क्षेत्र में उपज ले जाने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही भंडारण, जिसमें गोदाम में रखना भी शामिल है, उस पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण एलान में से एक जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने प्रोसेसर, एग्रीगेटर, बड़े खुदरा कारोबारियों और निर्यातकों के लिए कानूनी खाका तैयार करने की बात कही है। इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पर समझा जा सकता है। इस पर नजर रखना होगा कि यह कानून कैसे बनता है और इसमें राज्य किस तरह से सहयोग करते हैं।

इन सबके अलावा सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए भारत को और आकर्षक बनाने का एलान भी इस पैकेज में किया है। इसे आत्मनिर्भरता के साथ विदेशी कंपनियों को मेक इन इंडिया से जोड़ने की महत्वाकांक्षी कोशिश कह सकते हैं। कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की स्वीकृति दे दी गई है। इससे मिनरल क्षेत्र में ग्रोथ आएगी और रोजगार मिल सकेगा। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। माइनिंग लीज को ट्रांसफर किया जा सकेगा, इससे माइनिंग की गई खदानों को भी फिर से बेचा जा सकेगा। कोल के गैसीफिकेशन के लिए इंसेंटिव देना भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया बड़ा सुधार है। अभी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा

कोयला भंडार होने के बावजूद कोयला आयात करना पड़ता है, लेकिन अब कोयला खनन पर अब सरकार का एकाधिकार नहीं रहेगा। कोयला खनन पर 50 हजार करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गयी है। लेकिन हथियारों, रक्षा उपकरणों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पक्की योजना तैयार की गई है। इसके तहत प्रतिवर्ष हथियारों, मशीनों की सूची जारी होगी, जिसे सिर्फ भारतीय उत्पादकों से ही खरीदा जाएगा, लक्ष्य पूरी तरह से भारत में बने रक्षा उपकरण खरीदने का है। एमआरओ मेनटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की बात बजट में भी कही गई थी। अब सरकार इस अवसर का लाभ नये सिरे से लेने की बात कर रही है। एयरस्पेस, हवाई क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, अभी तक 60% हवाई क्षेत्र ही खुला हुआ है। हवाई क्षेत्र बढ़ाने से समय कम लगेगा और एटीएफ भी बचेगा। 6 विश्वस्तरीय हवाई अड्डे पीपीपी के तहत बन रहे हैं और 6 और एयरपोर्ट की नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 12 हवाई अड्डों की नीलामी से 13 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा। एएआई को 2,300 करोड़ का डाउन पेमेंट किया जाएगा। हेल्थ, रोजगार, शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों के लिए भी सरकार ने बड़े एलान किए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कई कदम उठाए हैं, जहां इंटरनेट नहीं है, वहां स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल से शिक्षा दी जाएगी। कुल 12 चैनल शिक्षा के लिए शुरू किए जाएंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में भी बच्चों को फायदा होगा। शिक्षा के लिए ई-विद्या पर फोकस किया जा रहा है, हर कक्षा की पढ़ाई के लिए 1 चैनल होगा।

कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान विशेष आर्थिक पैकेज सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में थोड़ी सी रकम देने या फिर कुछ जरूरतमंद के घर राशन पहुंचाने भर का पैकेज नहीं है बल्कि इसके जरिये भारत सरकार पहले सुस्त पड़ी और चाइनीज वायरस की वजह से एकदम से ठप सी हो गई अर्थव्यवस्था को नये सिरे से दौड़ाने की योजना बना रही है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देकर शहर और गांव के बीच के असंतुलन को दूर करके एक बेहतर भारत के निर्माण का प्रयास भी है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो है. लेख में व्यक्त उनके विचार निजी हैं.)

लॉक से अनलॉक का औचित्य

शिवानन्द द्विवेदी

कोविड महामारी की वजह से घोषित चार चरणों के लॉक डाउन के बाद अब देश 'अनलॉक 1.0' के पहले चरण में प्रवेश कर चुका है. दूसरे चरण का लॉक डाउन समाप्त होने के बाद जब तीसरे चरण की घोषणा हुई थी तभी 'अनलॉक' की तरफ बढ़ने के संकेत मिलने लगे थे. देश अब लॉक डाउन से निकलकर कोविड की चुनौतियों से लड़ते हुए कामकाज और जनजीवन को पटरी पर लाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है. कुछ पाबंदियों के साथ ज्यादातर बाजार, कारोबार और संस्थान खुल गये हैं. सरकार ने भी परिस्थितियों से उभरी बहुआयामी चुनौतियों के खिलाफ चौतरफा लड़ाई लड़ने की मंशा जाहिर कर दी है.

कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि ऐसे समय में लॉक डाउन क्यों खोला जा रहा जब कोविड के मामले बढ़ रहे हैं ? कुछ लोग यह सवाल करते भी दिख रहे हैं कि जब कोविड संक्रमित लोगों की संख्या सैकड़ों में थी तब लॉक डाउन लगाया गया और जब यह संख्या लाखों में पहुंच गयी तब हटाने का क्या औचित्य है ?

इन सवालों पर विचार करते हुए हमें इस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि 'लॉक डाउन' कोरोना वायरस का 'वैक्सीन' नहीं है. लॉक डाउन इसलिए भी नहीं लगाया गया कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा. लॉक डाउन का पहला लाभ यह हुआ कि कोरोना के सामुदायिक प्रसार की तीव्रता को नियंत्रित करने में दुनिया की तुलना में भारत को अधिक कामयाबी मिली. वैक्सीन इजाद होने की अनिश्चितता की स्थिति में भारत जैसे देश के लिए यह जरूरी था कि वह अपने स्वास्थ्य ढांचे को कोरोना की वजह से आने वाली भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके. भारत ने स्वयं को इस लिहाज से तैयार किया है.

इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि लॉक डाउन का नीतिगत निर्णय सरकार ने नहीं लिया होता तो कोविड अस्पतालों की उपलब्धता, पर्याप्त जांच की सुविधा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ एकसाथ खड़ी हो जाती. 24 मार्च को भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ने की रफ़्तार 21.6 फीसद थी, जो अब 5 फीसद से नीचे आ चुकी है. इस आधार पर देखें

तो यदि लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अप्रैल में ही 2 लाख से अधिक चुकी होती.

लॉक डाउन की वजह से इसके प्रसार की गति को कारगर ढंग से रोकने में देश को सफलता मिली है. इसका एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि सरकार ने भविष्य में खड़ी होने वाली चुनौतियों के लिए नेशनल हेल्थ सिस्टम के स्तर पर तैयारी की है.

कोविड के खिलाफ लड़ाई में जबतक कारगर इलाज नहीं खोज लिया जाता तबतक इस वायरस से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने की नीति पर चलना सभी देशों की मजबूरी है. इस मामले में भारत की नीतियां दुनिया के अनेक साधन संपन्न देशों की तुलना में अधिक कारगर नजर आती हैं. लॉक डाउन के दौरान सरकार ने वर्तमान स्थिति को संभालते हुए भविष्य में उभरने वाली चुनौतियों के लिए कई स्तरों पर बेहतर तैयारियां की हैं. वर्तमान में भारत में 1000 के आसपास कोविड के लिए आरक्षित अस्पताल हैं. लगभग 60 हजार वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है. प्रतिदिन 3 लाख पीपीई किट का उत्पादन हो रहा है. देश में 600 से अधिक टेस्टिंग लैब हैं, जिनमें प्रतिदिन 1 लाख 40 हजार तक सेंपल की जाँच हो रही है. यदि लॉक डाउन नहीं हुआ होता तो समय रहते इतनी व्यापक संरचना नहीं तैयार हो पाती.

सही समय पर कारगर निर्णय लेने का लाभ यह भी हुआ कि इटली जैसी स्थिति भारत में नहीं पैदा हुई. वर्तमान की स्थिति में भी भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में नजर आता है. एकतरफ जहां दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्युदर बहुत अधिक है वहीं भारत में यह आंकड़ा 3 फीसद से कम है. भारत इस मामले में भी कोरोना के खिलाफ बेहतर स्थिति में कहा जा सकता है कि यहां एक्टिव संक्रमित मरीज और ठीक हो चुके लोगों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है. 4 जून के आंकड़ों में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख 7 हजार है तो वहीं ठीक हो चुके लोगों की संख्या 1 लाख 5 हजार दर्ज हुई है. देश में लोगों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ते हुए 50 फीसद के करीब पहुंच चुकी है. शुरुआती लॉक डाउन नहीं हुआ होता तो शायद कोरोना का प्रसार गांवों तक हो चुका होता. किंतु इन दो महीनों में गाँव सजग और सतर्क हुए तथा बाहर से करोड़ों श्रमिकों के वापस जाने के बावजूद कोरोना का प्रसार गांवों में नहीं हुआ है.

अगर बात अनलॉक 1.0 की करें तो यह भी एक जरुरी नीतिगत कदम है. एक सौ तीस करोड़

की आबादी वाले देश को असीमित समय तक लॉक डाउन में नहीं रखा जा सकता. कामकाज को अधिक समय तक ठप रखने से देश को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. सरकार और समाज के मदद की एक सीमा है. उस सीमा को लांघने की कोशिश करने से देश की आर्थिक बुनियाद में दरार पैदा होगी. ऐसे में यह जरुरी है कि सावधानी और सतर्कता के अनुशासन का पालन करते हुए अब कामकाज को शुरू किया जाए.

दो महीने के लॉक डाउन में लोगों ने कोविड काल में जीवन के नए तौर-तरीकों को सीख लिया है. सतर्कता के नए अभ्यास लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. कामकाज की पद्धति में भी बदलाव आजमाया जा चुका है. कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझने के लिए देश अधिक सक्षम हुआ है. अब समय आ गया है भविष्य की चुनौतियों की तरफ बढ़ा जाए. लॉक डाउन करके कोरोना के दौर में सटीक निर्णयों से बेहतर परिणाम लाने वाली मोदी सरकार ने अनलॉक की तरफ बढ़कर भविष्य के भारत की नई चुनौतियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए जरूरी कदम उठाये हैं. प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' की कल्पना में भविष्य के बदलावों की आहट सुनाई दे रही है.

(लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो हैं. लेख में व्यक्त उनके विचार निजी हैं.)

रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती से आमजन को मिलेगी राहत

सतीश सिंह

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 मई को रेपो दर में 40 बीपीएस की कटौती करने से बैंक से कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलने का अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने बैंक से 40 लाख रूपये का कर्ज 20 सालों के लिये लिया है तो उसकी मासिक क़िस्त में 960 रूपये की कमी आयेगी और साल में 11,520 रूपये की बचत होगी। इस कटौती का फायदा खुदरा ऋण जैसे, गृह ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण अदि लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा।

रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई ताजा कटौती से यह घटकर 4.00 प्रतिशत हो गया है। रेपो दर वह दर होता है, जिसपर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। ताजा मौद्रिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो दर में भी कटौती की है, जिससे यह घटकर 3.35 प्रतिशत हो गया है। रिवर्स रेपो दर में इसलिये कटौती की गई है, ताकि बैंक बैंकिंग प्रणाली में आये सस्ती पूँजी का इस्तेमाल आमजन और कारोबारियों को ऋण देने के लिये करें।

बैंक जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को कर्ज देते हैं, उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। रिवर्स रेपो दर में कटौती करने से बैंक रिजर्व बैंक में पैसा जमा करने की जगह ग्राहकों को ऋण देने के लिये प्रोत्साहित होंगें, क्योंकि ग्राहकों को ऋण देने से उनके मुनाफे में तेजी आयेगी।

चूँकि, केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में कटौती करने से बैंकिंग प्रणाली में सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध है, इसलिये बैंकों को जमा और कर्ज दर के बीच के स्प्रेड को बनाये रखने के लिये जमा दरों में कटौती करनी होगी, क्योंकि बैंकों को जमा और कर्ज दर के बीच मौजूद अंतर से ही मुनाफा होता है।

नीतिगत दरों में कटौती करने के अलावा रिजर्व बैंक ने आमजन को राहत देने के लिये मियादी कर्ज अदायगी और कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर लगने वाले ब्याज अदायगी पर ऋण स्थगन की अवधि को भी तीन महीनों यानी 31 अगस्त, 2020 तक के लिये बढ़ा दिया है।

रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई से पहले किए गये आयात पर धन प्रेषण की अवधि को भी 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है। आयात और निर्यात के मोर्चे पर बेहतरी लाने के लिये रिजर्व बैंक ने एक्जिम बैंक को भी 15,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है।

माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा लिये गये इन निर्णयों से कोरोना महामारी से प्रभावित आमजन और कारोबारियों को राहत मिलेगी साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आयेगी।

कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प पड़ चुकी है। इसलिये, रिजर्व बैंक ने बैंकों को बड़े कारोबारियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने के लिये कहा है।

पूर्णबंदी के कारण पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र के भी कमजोर रहने की आशंका है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में मुद्रास्फीति को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। हालाँकि, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सरकार की सकारात्मक नीतियों की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में 15 मई तक 9.2 अरब डॉलर से बढ़कर 487 अरब डॉलर हो गया। बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत पूरी तरह से इसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है, जो आयात और निर्यात के कम या ज्यादा होने के आधार पर तय होता है।

अगर कोई देश ज्यादा निर्यात करता है तो उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार ज्यादा होता है। चूँकि, भारत निर्यात की जगह आयात ज्यादा करता है, इसलिये, यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडार हमेशा सीमित होता है। कम विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से रुपया डॉलर की तुलना में हमेशा कमजोर बना रहता है। इसलिये, विदेशी मुद्रा भंडार में बढोतरी होना अर्थव्यवस्था की सेहत के लिये बेहतर माना जाता है।

इसके पहले 27 मार्च, 2020 को रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 75 बीपीएस की कटौती की थी, जिससे बैंक से खुदरा ऋण लेने वालों को फ़ायदा हुआ था। अगर किसी ग्राहक ने उस समय 15 सालों के लिये लिये बैंक से 35 लाख रूपये ऋण लिये हुए थे तो उसे हर महीने 1,533 रूपये और सालाना 18,396 रूपये का फ़ायदा हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक समीक्षा के दौरान मियादी ऋणों पर क़िस्त एवं ब्याज की चुकौती और कार्यशील पूँजी के ऋण की ब्याज अदायगी को 3 महीनों के लिये स्थगित कर दिया था। साथ ही, संवाधिक तरलता अनुपात यानी सीआरआर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया था, जिससे बैंकिंग प्रणाली में 3.74 लाख करोड़ रूपये नकदी का प्रवाह हुआ था।

अब रेपो दर में की गई कटौती का फ़ायदा उन्हीं बैंक ग्राहकों को मिलेगा, जिनका उधारी खाता एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट (ईबीएलआर) से जुड़ा हुआ हो। गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 से सभी तरह के खुदरा

ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट (ईबीएलआर) से जोड़ा गया था। अगर किसी ग्राहक का खाता ईबीएलआर से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसे रेपो दर में की गई कटौती का फ़ायदा नहीं मिलेगा।

स्पष्ट है कि आरबीआई की इन ताज़ा पहलों से आमजन को राहत और आर्थिक गतिविधियों को रफ़्तार मिलने की उम्मीद है।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना संकट : गरीबों के हितों के साथ-साथ राज्य के विकास को लेकर भी सक्रिय है योगी सरकार

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश में आपदा को अवसर बनाने का अभियान आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना आपदा के शुरुआती समय में इसके लिए आह्वान किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। आपदा राहत प्रबन्धन के साथ ही निवेश, रोजगार, गरीब बच्चों की शिक्षा, एक्सप्रेस वे निर्माण सहित अनेक विकास कार्यों का भी संचालन किया जा रहा है।

इस क्रम में योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के माध्यम से कामगारों के खाते में एक-एक हजार रुपये ट्रांसफर किए। इससे प्रदेश में करीब साढ़े दस लाख श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिला है। करीब एक सौ करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कई मजदूरों से संवाद कर यह विश्वास दिलाया कि उन्हें जल्द रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा।

बीतें दिनों में करीब सत्रह सौ से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आईं। साथ ही, प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बारह हजार से अधिक परिवहन निगम की बस चलाई गईं। मजदूरों/कामगारों के मेडिकल स्क्रीनिंग व रहने खाने की व्यवस्था के लिए पन्द्रह लाख की क्षमता के क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए।

इन लोगों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए पहले चरण में दस लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के खाते में रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। बाकियों के भी बैंक एकाउंट डिटेल एकत्र करने का काम शीघ्रता से हो रहा है। सरकार सभी प्रवासियों के भरण पोषण हेतु कटिबद्ध है।

इनकी स्किल मैपिंग का काम हो चुका है। अब उन्हें जनपद स्तर पर मुस्तैदी के साथ रोजगार से जोड़ने का काम भी जारी है। जॉब कॉर्ड के अलावा स्किल के अनुसार जिला प्रशासन इनके रोजगार की व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा प्रथम चरण में प्रवासी कामगारों के लिए पन्द्रह दिन के राशन किट की व्यवस्था की गई। इसमें पर्याप्त आटा, चावल, आलू, भुना चना, अरहर दाल, तेल व मसाले शामिल थे।

गरीबों-मजदूरों के हितों की चिंता के साथ-साथ योगी राज्य की विकास सम्बन्धी गतिविधियों को लेकर भी सक्रिय हैं। एक्सप्रेस वे व औद्योगिक गलियारे के इस दौरान बाधित हुए कार्य में पुनः तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे का निर्माण विकास को गति देगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर तेजी से कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर को आजमगढ़ होते हुए लखनऊ से जोड़ेगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर गोरखपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से लखनऊ तक यात्रा करने में जो समय लगता है, उतना ही समय एक्सप्रेस वे के द्वारा गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में लगेगा।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से वाराणसी और गोरखपुर की यात्रा कम समय में की जा सकेगी और यह परियोजना पूर्वांचल के इन दो महत्वपूर्ण नगरों को और निकट ले आएगी। गंगा एक्सप्रेस वे के डीपीआर की कार्यवाही भी अंतिम चरण में है।

यह सभी एक्सप्रेस वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए आर्थिक विकास की धुरी बनेंगे। देखा जाए तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बना है। कनेक्टीविटी बेहतर हुई है। साथ ही, अगले वर्ष से गोरखपुर में एम्स भी पूरी तरह कार्य करने लगेगा।

इसके अलावा योगी आदित्यनाथ स्थानीय उत्पाद की ब्रांडिंग पर भी बल देते रहे हैं। चूंकि यह आम का

सीजन है, इसलिए उन्होंने आम की अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राण्डिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि इसकी गुणवत्ता के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।

आम के विपणन एवं निर्यात के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। सरकार आम उत्पादकों, निर्यातकों और किसानों के हितों व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पुराने बागों का जीर्णोद्धार, कोल्ड रूम की व्यवस्था, पैक हाउस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कीटनाशकों के छिड़काव के सम्बन्ध में किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही, आम के बागों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सरकार की योजना आम आधारित व्यवसायों की इकाईया स्थापित करवाने की है। अन्तर्राज्यीय विपणन के लिए हॉफेड, नैफेड एवं मण्डी परिषद योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करेंगे। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों तथा बागवानी के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक किस्मों को 'बायर-सेलर मीट' के माध्यम से प्रोत्साहित करने पर विचार किया जा रहा है।

आम की दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला, रटौल, सफेदा, गौरजीत, आम्रपाली, मल्लिका जैसी प्रजातियों की मांग है। अतः इनकी ब्राण्डिंग करते हुए निर्यात सम्बन्धी समस्याओं को दूर कर इस उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।

आम के अतिरिक्त किसानों को जैविक फसलें उगाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ इनकी प्रभावी मार्केटिंग करने की भी व्यवस्था किए जाने पर काम चल रहा है।

इसके अलावा योगी आदित्यनाथ श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर भी नजर बनाए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत यूपी के अनाथ बच्चों तथा मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बालकों को एक हजार रुपये प्रतिमाह और बालिकाओ को बारह सौ रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

जाहिर है, योगी आदित्यनाथ इस आपदकाल में भी न केवल इससे प्रभावित तबकों की हित-चिंता कर रहे हैं, अपितु राज्य के विकास के पहिये को भी बंद होने से बचाने पर उनका पूरा ध्यान है और इसके लिए उनकी सरकार लगातार कदम उठा रही है। यही कारण है कि आज यूपी कोरोना से लड़ने के मामले में देश के राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में नजर आ रहा है।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। स्वतंत्र रूप से पत्र-पत्रिकाओं और वेबपोर्टलों के लिए लिखते हैं। प्रस्तुत लेख में उनके निजी विचार हैं।)

अब जल शक्ति घर लौटे कामगारों का बनेगा आधार

नेशनलिस्ट टीम

भारत सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन को और तेज कर दिया है। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ कामगारों के लिए जीवन दायक मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती देने में भी यह अहम भूमिका निभा सकता है।

दरअसल, महामारी के चलते लाखों की तादाद में प्रवासी कामगार अपने घरों को लौट गए हैं। रोजगार के अभाव और परिवार के पोषण की जिम्मेदारी इनके लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीण विकास की ऐसी योजनाएं उनके जीवन को एक आधार देती दिख रही हैं।

अबतक ग्रामीण अंचलों में चल रहे मनरेगा और गरीबों की आवास योजनाओं ने लोगों को रोजी-रोटी के साथ इज्जत से जीना सिखाया है। अब जब केंद्र सरकार 'जल जीवन मिशन' को तेज करने का मन बना चुकी है, तो निश्चित रूप से घर लौटे इन हताश कामगारों के लिए यह रोजगार का बेहतरीन मौका साबित होगा। यही नहीं, ग्रामीणों के जल की समस्या को भी दूर करने में भी यह योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है।

विचार करें तो यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का बेहतरीन मौका है, जिसमें घर आए इन कामगारों की भूमिका अहम होगी। इस बात को केंद्र सरकार अच्छी तरह समझ रही है और यही मौका देखकर इस योजना को युद्ध स्तर पर चालू करने के प्रयास में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन पर काम शुरू कर दिया है।

ताजा हालात के मद्देनजर यह मिशन कई राज्यों के लिए राहत देने वाला होगा। इससे राज्यों की पेय जल की समस्याए का हल भी निकाला जा सकेगा, साथ ही घर वापस गए कामगारों को रोजगार भी दिया जा सकेगा।

यही नहीं, योजना में यह भी निर्णय लिया गया है कि पुरानी लंबित पड़ी ऐसी परियोजनाओं को भी इसके साथ शामिल किया जाए, जिनके लिए कुशल कामगारों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पलायन कर लौटे कामगारों की यहां खासी मांग रहेगी। बताते चलें कि शहरों से अपने अपने घरों की तरफ पलायन करने वाले ग्रामीणों में

40 प्रतिशत से अधिक वह कामगार हैं जो शहर के कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते थे और रोजी रोटी कमाते थे।

15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 60,750 करोड़ की ग्रांट मिलनी है, जिसका पचास प्रतिशत से ज्यादा भाग जलापूर्ति और स्वच्छता पर खर्च किया जाएगा। यह मिशन ग्राम पंचायतों, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी विभिन्न योजनाओं को मिले इस ग्रांट के उपयोग के तहत किया जाएगा। पूरी योजना लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ की है जिसमें केंद्र को दो लाख दस हजार और राज्यों को डेढ़ लाख करोड़ योगदान स्वरूप दिया जाएगा।

याद दिलाते चलें कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना की घोषणा की थी। इसलिए भी यह योजना केंद्र के लिए बेहद अहम है। महामारी के दौर में यह योजना राज्यों की जल समस्या का भी निदान करेगी और ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित कामगारों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी।

इस योजना की यदि मनरेगा से तुलना की जाए तो मनरेगा सिर्फ ग्रामीणों के लिए रोजगार का अवसर देता है, जबकि जल जीवन मिशन रोजगार के अलावा बाजार में मांग बढ़ाएगा तथा क्षेत्र का स्थायी ढांचा भी खड़ा करेगा।

यदि इस मिशन में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो जल्द ही लोगों को पर्याप्त मात्र में स्वच्छ पेय जल की सुविधा मिलेगी और देशभर में इस पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना की गंभीरता को इस बात से भी आंका जा सकता है कि इसके लिए अलग से आम बजट आवंटन किया गया है, जिससे मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

जहां तक गुणवत्ता की बात है, तो गांव व पंचायत स्तर पर जल की जांच के लिए किट मुहैया की जाएगी। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने की भी योजना है। यह युवक गांव के ही होंगे और इनकी संख्या पांच होगी।

जानना रोचक होगा कि दरअसल हमारे देश में अप्रैल 2019 तक 19.04 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ घरों में ही नल से सप्लाई पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में यदि यह योजना सलीके से अपना काम करती जाती है, तो पेय जल की आपूर्ति से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो पाएंगे।

मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे, वो कांग्रेसी सरकारों के एजेंडे में कभी था ही नहीं

रमेश कुमार दूबे

12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बीस लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एलान किया। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार की बात कही ताकि आत्मनिर्भर भारत का ख्वाब हकीकत में बदल सके। अब तक राहत पैकेजों का फोकस सामान्यत: बड़े उद्यमों पर रहता था लेकिन इस बार सरकार ने देश भर में फैले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्राथमिकता दी है।

इसी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए राहत पैकेज का एलान किया है। इसके तहत एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करते हुए 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को सूक्ष्म उद्योग, 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को लघु उद्योग और 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों को मध्यम उद्योग का दर्जा दिया गया है। घरेलू खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि 200 करोड़ रूपये तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। इसके अलावा एमएसएमई को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा ताकि ये उद्यम लोकल से ग्लोबल बन सकें।

गौरतलब है कि भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। यह क्षेत्र जमीनी ग्रामोद्योग से शुरू होकर ऑटो कल-पुर्जे के उत्पाद, माइक्रोप्रोसेसर, इलेक्ट्रानिक उपकरणों और विद्युत चिकित्साल उपकरणों तक फैला हुआ है। देश के विनिर्माण क्षेत्र में इस क्षेत्र की 45 प्रतिशत हिस्सेसदारी है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में यह 8 प्रतिशत योगदान करता है। यह क्षेत्र बारह करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

इन बहुआयामी लाभों के बावजूद एमएसएमई पूंजी की कमी से जूझता रहा है। इसका कारण है कि

राष्ट्रीयकरण के बावजूद बैंकों का ढांचा अमीरों के अनुकूल और गरीबों के प्रतिकूल ही बना रहा। इस कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक की स्थापना की जिसके तहत छोटे उद्यमियों को पचास हजार से लेकर दस लाख रूपये तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके लाभार्थियों में छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लोग शामिल हैं जैसे फल-सब्जी विक्रेता, मैकेनिक, नाई, ब्यूटीपार्लर, दर्जी, कुम्हार, मोची आदि।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश के एमएसएमई क्षेत्र को 59 मिनट में अर्थात एक घंटे से भी कम समय में एक करोड़ रूपये तक का ऋण मुहैया कराने वाले पोर्टल को लांच किया है। इसके अलावा कई जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया।

इसके बावजूद छोटे उद्यमियों की चुनौतियाँ दूर नहीं हुई थीं। इसी को देखते हुए सरकार एमएसएमई क्षेत्र को तीन लाख करोड़ रूपये का पैकेज दे रही है। एमएसएमई के कर्ज में सबसे बड़ी बाधा गारंटर की होती है जिसे दूर करते हुए सरकार ने इन इकाइयों को बिना गारंटी लोन की व्यरवस्था की है। इस लोन की समय सीमा चार वर्ष होगी। इसके अलावा संकटग्रस्त इकाइयों के लिए 20,000 करोड़ रूपये की नकदी की व्यवस्था की गई है।

दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है, वह अब तक अधिकांश समय तक सत्ता में रही कांग्रेसी सरकारों की प्राथमिकता में कभी था ही नहीं। पहले घरेलू उद्योगों के विकास के नाम पर संरक्षणवादी नीतियां अपनाई गईं लेकिन संरक्षण के नाम पर भ्रष्ट नेताओं-नौकरशाहों-ठेकेदारों की तिकड़ी ने समाजवादी नीतियों को साम्राज्य वादी नीतियों में बदल डाला। नतीजा गरीबी, बेकारी, उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद में तेजी से इजाफा हुआ।

1991 में शुरू हुई नई आर्थिक नीतियों में उदारीकरण-भूमंडलीकरण के नाम पर महानगर केंद्रित विकास रणनीति की शुरूआत हुई। इसमें विकास का रथ महानगरों और हाईवे से आगे बढ़ ही नहीं पाया। इससे देश भर में फैले करोड़ो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की घोर उपेक्षा हुई। मुक्त व्यापार नीतियों को इस तरह बनाया गया कि सत्तापक्ष से जुड़े बिचौलिए और उद्योगपतियों के लिए कर मुक्त आयात सुविधाजनक हो गया।

इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि देश भर के बाजार विदेशी विशेषकर चीन में बने सामानों से भर गए। इसका नतीजा यह हुआ कि अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले करोड़ो लघु व कुटीर उद्योग घाटे में चले गए। इससे इन उद्यमों में नियोजित कामगारों के पास महानगरों की ओर पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।

जो कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन में करोड़ो कामगारों के गांव लौटने की खबर को प्रमुखता से उठा रही है उसे यह बताना चाहिए कि क्या ये प्रवासी पिछले छह वर्षों में महानगरों में आए हैं? यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने

यूपीए-2 के तीन वर्ष पूरा होने पर जो जश्न मनाया था उसमें एक प्लेट खाने की कीमत 7721 रूपये थी।

दूसरी ओर यूपीए सरकार ने 2011 में गांव और शहर में गरीबी रेखा के निर्धारण में महज एक रूपये की बढ़ोत्तरी करके क्रमश: 27.20 रूपये और 33.30 रूपये कर दिया था। इससे देश में गरीबों की संख्या 40.73 करोड़ से कम होकर 26.89 करोड़ रह गई थी लेकिन जमीन पर गरीबी जस की तस रही। आत्मनिर्भर भारत पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को बताना चाहिए कि दिल्ली का सदर बाजार चाइना बाजार में कैसे तब्दील हो गया?

समग्रत: मोदी सरकार देश भर में फैले करोड़ो लघु व कुटीर उद्योगों को देश की आर्थिक धुरी में तब्दील कर रही है। इसके पूरा होने पर न केवल देश का संतुलित विकास होगा बल्कि गरीबी, बेकारी, असमानता, महानगरों की ओर पलायन जैसी कांग्रेस द्वारा पैदा की गई समस्याएं भी दूर होंगी।

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

विज्ञान ही नहीं, अध्यात्म के जरिये भी कोरोना से लड़ रहा भारत

नीलम महेंद्र

शक्ति कोई भी हो दिशाहीन हो जाए तो विनाशकारी ही होती है लेकिन यदि उसे सही दिशा दी जाए तो सृजनकारी सिद्ध होती है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल को सभी देशवासियों से एकसाथ दीपक जलाने का आह्वान किया जिसे पूरे देशवासियों का भरपूर समर्थन भी मिला। जो लोग कोरोना से भारत की लड़ाई में प्रधानमंत्री के इस कदम का वैज्ञानिक उत्तर खोजने में लगे हैं वे निराश हो सकते हैं क्योंकि विज्ञान के पास आज भी अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं।

हाँ, संभव है कि दीपक की लौ से निकलने वाली ऊर्जा देश के 130 करोड़ लोगों की ऊर्जा को एक सकारात्मक शक्ति का वो आध्यात्मिक बल प्रदान करे जो इस वैश्विक आपदा से निकलने में भारत को संबल दे। क्योंकि संकट के इस समय भारत जैसे अपार जनसंख्या लेकिन सीमित संसाधनों वाले देश की अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा हथियार है जो कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकता है तो वो है हमारी "एकता"। और इसी एकता के दम पर हम जीत भी रहे थे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डॉ डेविड नाबरो ने भी अपने ताज़ा बयान में कहा कि भारत में लॉक डाउन को जल्दी लागू करना एक दूरदर्शी सोच थी,साथ ही यह सरकार का एक साहसिक फैसला था। इस फैसले से भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का मौका मिला।

लेकिन जब भारत में सबकुछ सही चल रहा था, जब इटली, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका जैसे विकसित एवं समृद्ध वैश्विक शक्तियाँ कोरोना के आगे घुटने टेक चुकी थीं, जब विश्व की आर्थिक शक्तियाँ अपने यहाँ कोविड 19 से होने वाली मौतों को रोकने में बेबस नज़र आ रही थीं, तब 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 500 के आसपास थी और इस बीमारी के चलते मरने वालों की संख्या 20 से भी कम थी, तो अचानक तब्लीगी मरकज़ की लापरवाही सामने आती है जो केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशों की धज्जियाँ उड़ाते हुए निज़ामुद्दीन की मस्जिद में 3500 से ज्यादा लोगों के साथ एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन करती है।

16 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाते हैं, 22 मार्च को प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू की अपील करते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बताते हैं लेकिन मार्च के आखिरी सप्ताह तक इस मस्जिद में 2500 से भी ज्यादा लोग सरकारी आदेशों का मख़ौल उड़ाते इकट्ठा रहते हुए पाए जाते हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार मस्जिद को खाली कराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सामने आना पड़ा था क्योंकि ये स्थानीय प्रशासन की नहीं सुन रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अबतक सामने आए 4067 मामलों में 1445 मामले तबलीगी जमात से संबंधित हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं वो केवल निराशाजनक ही नहीं शर्मनाक भी हैं क्योंकि इस मरकज़ की वजह से इस महामारी ने हमारे देश के कश्मीर से लेकर अंडमान तक अपने पैर पसार लिए हैं।

देश में कोविड 19 का आंकड़ा अब चार दिन के भीतर ही 4000 को पार कर चुका है, सौ से अधिक लोगों की इस बीमारी के चलते जान जा चुकी है और इस तब्लीगी जमात की मरकज़ से निकलने वाले लोगों के जरिए देश के 17 राज्यों में कोरोना महामारी अपनी दस्तक दे चुकी है।

देश में पहली बार एक ही दिन में कोरोना के 600 से ऊपर नए मामले दर्ज किए गए। बात केवल इतनी ही होती तो उसे अज्ञानता, नादानी या लापरवाही कहा जा सकता था लेकिन जब इलाज करने वाले डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला किया जाता है या फिर उन पर थूका जाता है जबकि यह पता हो कि यह बीमारी इसी के जरिए फैलती है या फिर महिला डॉक्टरों और नरसों के साथ अश्लील हरकतें करने की खबरें सामने आती हैं तो प्रश्न केवल इरादों का नहीं रह जाता। ऐसे आचरण से सवाल उठते हैं सोच पर, परवरिश पर, नैतिकता पर, सामाजिक मूल्यों पर, मानवीय संवेदनाओं पर। किंतु इन सवालों से पहले सवाल तो ऐसे पशुवत आचरण करने वाले लोगों के इंसान होने पर ही लगता है।

क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में इनकी गुंडागर्दी करती हुई तस्वीरें कैद होती हैं तो कहीं फलों, सब्ज़ियों और नोटों पर इनके थूक लगाते हुए वीडियो वायरल होते हैं। ये कैसा व्यवहार है? ये कौन सी सोच है? ये कौन से लोग हैं जो किसी अनुशासन को नहीं मानना चाहते? ये किसी नियम किसी कानून किसी सरकारी आदेश को नहीं मानते। अगर मानते हैं तो फतवे मानते हैं। जो लोग कुछ समय पहले तक संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे वो आज संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।

पूरा देश लॉक डाउन का पालन करता है लेकिन इनसे सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करते ही पत्थरबाजी और गुंडागर्दी हो जाती है। लेकिन ऐसा खेदजनक व्यवहार करते वक्त ये लोग भूल जाते हैं कि इन हरक़तों से ये

अगर किसी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं तो खुद को और अपनी पहचान को। चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है। कुछ जाहिल लोग पूरी जमात को जिल्लत का एहसास करा देते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि असली गुनहगार वो मौलवी और मौलाना होते हैं जो इन लोगों को ऐसी हरकतें करने के लिए उकसाते हैं।

तब्लीगी जमात के मौलाना साद का वो वीडियो पूरे देश ने सुना जिसमें वो तब्लीगी जमात के लोगों को कोरोना महामारी के विषय में अपना विशेष ज्ञान बाँट रहे थे। दरअसल किसी समुदाय विशेष के ऐसे ठेकेदार अपने राजनैतिक हित साधने के लिए लोगों का फायदा उठाते हैं। काश ये लोग समझ पाते कि इनके कंधो पर देश की नहीं तो कम से कम अपनी कौम की तो जिम्मेदारी है। कम पढ़े लिखे लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाकर उनको ऐसी हरकतों के लिए उकसाकर ये देश का नुकसान तो बाद में करते हैं, पहले अपनी कौम और अपनी पहचान का करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का जमाना है और जमाना बदल रहा है। सच्चाई वीडियो सहित बेनकाब हो जाती है।

शायद इसलिए उसी समुदाय के लोग खुद को तब्लीगी जमात से अलग करने और उनकी हरकतों पर लानत देने वालों में सबसे आगे थे। सरकारें भी ठोस कदम उठा रही हैं। यही आवश्यक भी है कि ऐसे लोगों का उन्हीं की कौम में सामाजिक बहिष्कार हो साथ ही उन पर कानूनी शिकंजा कसे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनावृत्ति रुके। इन घटनाओं पर सख्ती से तुरंत अंकुश लगना बेहद जरूरी है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में हमने देखा कि तब्लीगी जमात की सरकारी आदेशों की नाफरमानी से कैसे हम एक जीतती हुई लड़ाई को मुश्किल कर बैठे हैं।

लेकिन ये अंत नहीं मध्यांतर है क्योंकि ये वो भारत है जहाँ की सनातन संस्कृति निराशा के अन्धकार को विश्वास के प्रकाश से ओझल कर देती है। आखिर अँधेरा कैसा भी हो एक छोटा सा दीपक उसे हरा देता है तो भारत में तो उम्मीद की एक सौ तीस करोड़ किरणें मौजूद हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन का महत्व विपक्ष भले न समझे, मगर आम लोगों ने बखूबी समझ लिया है

नवोदित सक्तावत

कोरोना महामारी संकट के चलते हुए लॉकडाउन के चार चरण गुजर जाने के बाद अब देश में अनलॉक का पहला चरण चल रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी तब वह एक आपात निर्णय था और कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण से देशवासियों को बचाने का इससे श्रेष्ठ एवं अहम निर्णय दूसरा नहीं हो सकता था।

इसके बाद लगातार दो महीनों तक भय का माहौल रहा। डराने वाले आंकड़े आते रहे लेकिन अब जाकर पिछले एक पखवाड़े में ऐसा लगा है मानो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई अर्थ पा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मय आंकड़ों के यह तस्दीक की जा रही है कि देश में अब रिकवरी रेट सुधर रहा है।

मौजूदा संक्रमण के मामलों में से लगभग आधे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं एवं शेष आधे एक्टिव केस हैं। इन सब बातों को सुनकर, पढ़कर अब लग रहा है कि मोदी सरकार की दूरदर्शिता एवं कड़ी मेहनत ने देश को एक अभूतपूर्व संकट से बचाया है। यदि समय पर लॉकडाउन लगाने एवं इसको बढ़ाने के सख्त फैसले ना लिए जाते तो भारत की विराट जनसंख्या के मान से मृतकों का आंकड़ा अत्यधिक हो सकता था।

यह साफ़ है कि इस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन ही बेहतर विकल्प था, जिसके जरिये न केवल संक्रमण की चेन को काफी हद तक तोड़ा जा सका बल्कि तैयारियों के लिए भी सरकार को वक्त मिल गया। लेकिन लॉकडाउन के शुरूआती दौर में देश के विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा जिस तरह इसपर सवाल उठाए गए वो विचित्र ही था।

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यह कहती दिखीं कि लॉकडाउन को लेकर सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। वहीं ममता बनर्जी लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर कभी गंभीर नजर नहीं आई।

सपा के अखिलेश यादव यह कहते दिखे कि लॉकडाउन से जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसलिए सरकार को विधानसभा का संयुक्त सत्र बुलाकर समस्या के समाधान के लिए विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। जाहिर है, विपक्षी दलों ने लॉकडाउन जैसे बेहद जरूरी निर्णय पर खुलकर सरकार साथ नहीं दिया और जिस-तिस प्रकार इसपर सवाल ही उठाते रहे।

जब विपक्ष यह सब कर रहा था, उसी समय 'जन की बात' के सम्पादक प्रदीप भण्डारी गांवों में जाकर लोगों से लॉकडाउन के औचित्य और उनकी समस्याओं आदि पर बातचीत कर रहे थे। प्रस्तुत वीडियो में प्रदीप उत्तर प्रदेश के सबोदा गाँव के लोगों से लॉकडाउन-2 को लेकर उनकी राय जान रहे तथा लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इसकी पड़ताल भी कर रहे हैं।

वीडियो की शुरुआती बातचीत में जेवर जिले में वाहन चालक के रूप में काम करने वाले ग्रामीण से जब प्रदीप पूछते हैं कि सरकार से मदद मिल रही है, तो जवाब हां होता है। साथ ही उस व्यक्ति का यह भी कहना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए।

आगे की बातचीत में बुजुर्ग शख्स यह तो मान रहे कि समस्याएँ हैं, लेकिन बावजूद इसके वे लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं तथा मानते हैं कि 'सरकार बढ़िया कर रही है'। जेवर में भवन निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने वाले हरेन्द्र कहते हैं कि इस दौरान फिलहाल काम तो बंद है लेकिन संतुष्टि है कि हमें खाने पीने को मिल रहा है। उनकी पत्नी के खाते में सरकार की जन कल्यांणकारी योजनाओं के पैसे आए हैं जिससे आपात समय में भी मदद मिल रही है।

कोरोना के कारण नोएडा से गाँव लौटे एक नौकरीपेशा शख्स का कहना है कि कोरोना जिस तरह की संक्रामक बीमारी है, उसे देखते हुए लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। गांव के लोगों का संयुक्त स्वर यही है कि लॉकडाउन वायरस से लड़ने के लिए ही लगाया गया है और वे इसके समर्थन में हैं। इस बातचीत में यह भी निकलकर आता है कि गाँव में लोग न केवल लॉकडाउन को ठीक मानते हैं, बल्कि उसका पालन भी कर रहे हैं।

वीडियो को देखते हुए समझा जा सकता है कि जब विपक्षी दल लॉकडाउन को लेकर नुक्ताचीनी करने में व्यस्त थे, तब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग समस्याओं-परेशानियों के बावजूद लॉकडाउन के पक्ष में थे और सरकार का समर्थन कर रहे थे।

मगर विडंबना ही है कि जो बात देश के गांवों में बसने वाले इन सामान्य लोगों को समझ में आ गयी, वो देश के बड़े विपक्षी दल और उनके प्रबुद्ध नेता अपनी संकीर्ण राजनीति के कारण नहीं समझ सके। ऐसे में, इस वीडियो का यह सन्देश विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में जनता सरकार और उसके निर्णयों के साथ है, वे चाहें जो कहते रहें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

गेम चेंजर साबित हो सकता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान

प्रहलाद सबनानी

भारत में कोरोना महामारी की वजह से लाखों की संख्या में श्रमिक विभिन्न महानगरों से गृह राज्यों की तरफ़ रवाना हुए थे। इन श्रमिकों के गावों में पहुँचने के बाद उन्हें रोज़गार प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 से ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान की शुरुआत की है।

इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के खगड़िया से की है. इस अभियान को विशेष रूप से महानगरों से पलायन किए लगभग 67 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रारम्भ किया गया है ताकि इन्हें गावों में न केवल रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके बल्कि इन गावों में परिसंपतियों का निर्माण भी किया जा सके।

ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान को लागू करने के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया है। ये 6 राज्य हैं – उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओड़ीसा एवं झारखंड। 30 मई, 2016 तक जिन जिलों में 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक महानगरों से वापिस ग्रामों में आए थे, उन जिलों का चयन इस अभियान को लागू करने के लिए किया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत रोज़गार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 25 मुख्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं एवं इन क्षेत्रों से सम्बंधित मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया है। इन श्रमिकों को गावों में ही रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह अभियान अगले 125 दिनों तक चलेगा एवं इस अभियान के लिए 50,000 करोड़ रुपए के फ़ंड की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों यथा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय का एक समन्वित प्रयास होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है।

दरअसल इस तरह के रोज़गार अभियान की देश में बहुत लम्बे समय से ज़रूरत थी। महानगरों से ग्रामों की ओर पलायन किए गए श्रमिकों में से दो तिहाई पलायनकर्ता श्रमिक कुशल हुनर वाले हैं। इसलिए यह विशेष योजना कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के लिए ही लाई गई है। दूसरी ओर अकुशल श्रमिकों के लिए पूर्व में ही मनरेगा योजना गावों में कार्यरत है जिसके अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को रोज़गार प्रदान किया जाता है।

इस नयी योजना के अंतर्गत कुशल श्रमिकों को गावों में ही उनके कौशल के अनुसार उसी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँगे ताकि वे ग्राम भी इनके कौशल का लाभ उठा सकें। इससे गावों में आधारिक संरचना भी मज़बूत होगी। साथ ही, सरकार जब इतनी बड़ी राशि ख़र्च करेगी और इन श्रमिकों के हाथों में पैसा आएगा तो इससे विभिन्न उत्पादों की माँग में भी वृद्धि होगी। यह ख़र्च मिशन मोड में होने जा रहा है और 125 दिन में यह पैसा व्यवस्था तंत्र में आ जाएगा।

राज्य सरकारें इन प्रवासी श्रमिकों के कौशल की मैपिंग करेंगी और इनके कौशल के आधार पर प्रयास करेंगी कि उन्हें उनके कौशल के अनुसार रोज़गार मिले। यदि कुछ श्रमिक अकुशल हैं, तो उन्हें इसी आधार पर कार्य प्रदान कराया जाएगा। प्रवासी कुशल श्रमिकों का महानगरों से पलायन देश के लिए एक अवसर भी माना जाना चाहिए क्योंकि जब ये कुशल श्रमिक गावों में आए हैं तो इनकी कुशलता का उपयोग करते हुए इन ग्रामों को भी लाभ दिलवाये जाने का प्रयास हो रहा है।

इस प्रकार, लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों के कौशल का अनुकूलतम उपयोग गावों में भी जारी रहेगा एवं देश इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों के कौशल के उपयोग से वंचित नहीं रह पाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन करवाया जाना है। अतः इस योजना को सफल बनाने का लिए राज्य सरकारों को केंद्र बिंदु बनाया गया है। केंद्र सरकार ने इस सम्बंध में दिशा निर्देश राज्य सरकारों को जारी कर दिए हैं। प्रवासी श्रमिक निकटतम ग्राम पंचायत से सम्पर्क करेंगे ताकि उनको उनके कौशल के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जा सके।

महानगरों से पलायन करने वाले श्रमिकों की पूरी सूची तैयार कर ली गई है और इस सूची में इन श्रमिकों के कौशल का ज़िक्र भी किया गया है, ताकि इनको इसी क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए। अतः इस बात की पूरी सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि यह अभियान अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल होगा। देश के आर्थिक विकास में गावों में उत्पादों की माँग का बहुत अच्छा ख़ासा प्रभाव रहता है।

इस वर्ष चूँकि मानसून की बारिश समय पर प्रारम्भ हो गई है एवं इसका फैलाव भी बड़ी तेज़ी से पूरे देश में हो रहा है। अतः इस वर्ष कृषि की पैदावार भी बहुत अच्छी होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। मनरेगा

योजना के लिए भी केंद्र सरकार ने धनराशि का आवंटन बढ़ा दिया है।

साथ ही, ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान के अंतर्गत भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि ख़र्च की जा रही है तो कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से इस वर्ष बहुत पैसा पहुँच रहा है। इस सबका मिलाजुला असर यह होगा कि इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र से उत्पाद की भारी माँग उत्पन्न होगी। अतः देश की अर्थव्यवस्था में जिस कमी के होने के बात की जा रही है उसकी पूर्ति इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था से हो जाएगी, इस बात की सम्भावना अब स्पष्टतः दिखने लगी है।

देश की अर्थव्यवस्था में शीघ्र ही शायद एक परिवर्तन और हो सकता है। चूँकि देश की 60 प्रतिशत आबादी आज भी गावों में निवास करती है अतः कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में गावों में ही उपलब्ध हैं। इस कारण शायद अब उद्योग क्षेत्र अपनी औद्योगिक इकाईयों को गावों के आस पास स्थापित करें क्योंकि उन्हें कुशल एवं अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक तो गावों से ही मिलने हैं।

इस प्रकार के पुनर्संतुलन की आवश्यकता बहुत लम्बे समय से महसूस की जा रही है। अब यह समय आ गया है कि उद्योग जगत मज़दूरों के पास पहुँचे। इससे न केवल गाँवों से शहरों की ओर हो रहे मज़दूरों के पलायन को रोका जा सकेगा बल्कि इस क़दम से ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी। अंततः इससे समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी शीघ्रता से हासिल किया जा सकेगा।

(लेखक बैंकिंग क्षेत्र से सेवानिवृत्त हैं। आर्थिक विषयों के जानकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार द्वारा समय के साथ लिए गए निर्णयों को समझने की आवश्यकता है

सन्नी कुमार

यह सच है कि कोरोना वायरस की मार से विश्व का कोई भी देश बच नहीं सका है, लेकिन यह भी सच है कि इसका असर सभी पर एक समान नहीं पड़ा है। जहाँ कुछ देशों में इसका सीमित असर पड़ा तो वहीं कुछ देशों को इस दौरान हुई मानवीय और भौतिक क्षति से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। शायद तब भी इसकी भरपाई न हो सके, मानवीय क्षति को तो वापस नहीं लौटाया जा सकता है। इन सब में एक बात जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो यह कि विभिन्न देशों ने इससे लड़ने की रणनीति क्या बनाई और कितनी सक्रियता से इसका पालन किया? कोरोना के विरुद्ध सफलता-असफलता में सबसे बड़ी भूमिका सरकारी प्रयासों की ही रही है। इसी संदर्भ में हम प्रस्तुत लेख के माध्यम से यह देखने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार ने इससे निपटने की क्या रणनीति अपनाई और वो कितनी सफल रही? इसे हम तीन अलग -अलग शीर्षकों के तहत समझने की कोशिश करेंगे जो क्रमशः इसके प्रसार को सीमित करने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और आर्थिक स्थितियों को सुधारने से संबंधित है।

ब्रेक द चेन पॉलिसी

नई बीमारी कोविड-19 की सबसे बुनियादी बात यह है कि यह संपर्क से फैलती है। यानी मनुष्यों के बीच आपसी संपर्क जितना सघन होगा इसके प्रसार की दर उतनी ही तीव्र होगी। इसी प्रकार इसके प्रसार से जुड़ा यह तथ्य भी उतना ही बुनियादी है कि चीन ने इसके प्रसार को रोकने में कोई मदद नहीं की, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि इस संबंध में पूरे विश्व को गुमराह किया और प्रकारान्तर से इसके प्रसार में योगदान दिया। चीन ने वर्ष 2019 के अंतिम दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को बड़े पैमाने पर 'अनजान कारकों' से हो रहे वायरल बीमारी, जिसका केंद्र वुहान था, की जानकारी दी। चीन ने वर्ष 2019 में ही यह निश्चित कर दिया था कि अगला वर्ष कैसा होना है! 'अनजान कारकों' का हवाला देने वाले चीन से दुनिया देखते ही देखते एक निश्चित संकट में फंस चुकी

थी। बहरहाल, नए साल के पहले सप्ताह के अंतिम दिन चीन में घोषित रूप से पहला 'कोविड' रोगी मिला। अब यहाँ से हम इस बात की पड़ताल कर सकते हैं कि जब दुनिया को 'घोषित' रूप से इस बीमारी का पता चला तो भारत सरकार ने इसके प्रति कितनी सक्रियता दिखाई।

वस्तुतः, इस घटना के ठीक एक दिन बाद यानी 8 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने विशेषज्ञों की पहली बैठक की। इसके बाद भारत ने तय किया कि चीन से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि संदेहास्पद लोगों को अलग किया जा सके। यह प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू हो गई, यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस समय तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने न तो इसे 'वैश्विक स्वास्थ्य आपदा' घोषित किया था और न ही इसे 'पेंडेमिक' ही कहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को इसे 'अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा (PHEIC)' घोषित किया और फरवरी के पहले सप्ताह से ही भारत सरकार ने विदेश में फंसे लोगों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

फरवरी के तीसरे दिन चीन की यात्रा से संबंधित 'ट्रैवल एडवाइजरी' जारी की गई और चीन के लिए ई-वीजा को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सिंगापुर के लिए भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई तथा नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया तथा मलेशिया से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग निश्चित की गई। ये सभी वैसे पोटेंशियल देश थे जहाँ से इसके प्रसार का खतरा अधिक था। 3 मार्च को जब भारत में मात्र 6 केस ही थे तभी सभी देशों से आने वाले यात्रियों की जॉच करने की नीति बनाई गई। इसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने होली मिलन न करने का निर्णय लिया। इसके बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया तथा अंततः 24 मार्च को भारत सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन का निर्णय लिया जो अब चौथे चरण में 31 मई तक कर दिया गया है। इस प्रकार भारत ने पूरी तत्परता दिखाई कि इसका संक्रमण न फैले। इस निर्णय का सकारात्मक असर भी देखने को मिला। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जहाँ 30 जनवरी को भारत में कोरोना का 1 मरीज था, यूके में एक भी नहीं, जर्मनी में 4, फ्रांस तथा अमेरिका में 5 मरीज थे वहीं 18 मई को अमेरिका में लगभग 15 लाख, यूके में 2.5 लाख, जर्मनी में 1.75 लाख, फ्रांस में 1.5 लाख मामले हो गए वहीं भारत में यह अभी 1 लाख से कुछ नीचे है। यहाँ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उपरोक्त सभी देश स्वास्थ्य सेवाओं में भारत से कहीं अधिक समृद्ध हैं, फिर भी प्रभाव की दृष्टि से अधिक पीड़ित हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार इसके प्रसार को रोकने में एक हद तक सफल रही है।

चिकित्सीय तैयारी

लॉकडाउन का यह फायदा हुआ कि संक्रमण कम फैला, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इस दौरान चिकित्सीय सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। क्योंकि अंततः बेहतर इलाज से ही इसपर विजय प्राप्त की जा

सकती है। इस संदर्भ में देखें तो भारत सरकार ने काफी सक्रियता दिखाई तथा आवश्यक स्वास्थ्य तैयारी को लेकर गंभीर दिखी। भारत में किसी भी मामले के आने के पूर्व ही सरकार ने कोरोना से निपटने के 2 महत्वपूर्ण उपकरण 'पीपीई किट' तथा 'एन-95 मास्क' के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही उन संभावित दवाओं को जो इसके उपचार में काम आने वाले थे उनके निर्यात को भी रोक दिया गया। 30 जनवरी को जब भारत में पहला केस दर्ज किया गया तभी 6 टेस्टिंग लैब को चिन्हित किया जा चुका था। शुरुआती स्थिति के बाद आज देखें तो स्थिति काफी नियंत्रण में है। सबसे पहले एक बात जो सर्वाधिक प्रमुखता से कही जा रही है वो यह कि अधिक से अधिक टेस्ट ही इससे लड़ने का सबसे कारगर उपाय है। इस लिहाज से आज भारत विश्व में सर्वाधिक टेस्टिंग के मामले में दूसरे नंबर पर है तथा इससे आगे सिर्फ अमेरिका है। भारत में अब तक 36 लाख से अधिक लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है तथा प्रतिदिन टेस्टिंग की क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है।

वस्तुतः जहाँ जनवरी में कोविड टेस्टिंग की सिर्फ एक लैब हुआ करती थी वहीं अब सरकारी तथा प्राइवेट मिलाकर 662 के करीब हो चुकी है। 27 मई 2020 तक 930 से अधिक कोविड समर्पित अस्पताल इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जबकि 7 हज़ार से अधिक कोविड देखभाल केंद्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अब भारत प्रतिदिन 2-2 लाख से अधिक पीपीई किट्स और एन-95 मास्क का उत्पादन कर रहा है तथा अब तक केंद्र सरकार ने राज्यों तथा अन्य केंद्रीय संस्थाओं को 113 लाख एन-95 मास्क और 89 लाख पीपीई किट्स उपलब्ध कराए हैं। यह बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ही है कि भारत में स्वस्थ होने की दर 42 प्रतिशत से अधिक है। साथ ही मामलों के दुगुने होने की दर भी अब बढ़कर 18 दिन हो चुकी है।

कुल मिलाकर कहें तो सरकार ने इस मोर्चे पर इतनी सक्रियता दिखाई है कि हालात नियंत्रण में बने हुए हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट में भारत की तैयारी की प्रशंसा की गई है।

आर्थिक नीति

कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार के आर्थिक प्रयासों को दो हिस्सों में देखने की जरूरत है। एक तब जब एकदम शुरुआती समय सरकार ने लगभग पौने दो लाख करोड़ रूपये का पैकेज जारी किया था। यह मुख्य रूप से अति संवेदनशील वर्गों को लक्षित था, जिनके लिए रोजमर्रा का काम बंद हो जाने से संकट आ गया था। दूसरा तब जब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज घोषित किया, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को उबारने की कोशिश की गई।

पहले हिस्से की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसके तहत प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया। फिर, 80 करोड़ गरीबों को तीन महीने तक हर माह

5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दाल उपलब्ध कराकर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 3.2 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक), विधवाओं और दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय भी लिया गया। इसके अतिरिक्त किसानों, मजदूरों को नकदी सहायता, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरण इत्यादि जैसे कदम ऐसे थे जो देखने में छोटे लग रहे थे पर करोड़ो परिवारों के लिए ये सहारा बने।

इसके बाद 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत जिस बहुआयामी नीतियों की घोषणा की गई वो निश्चित ही उत्साहजनक हैं। एक तरफ जहाँ विपक्षी जीडीपी के 1-2 प्रतिशत खर्च की बात कर रहे थे वहीं यह राशि जीडीपी का तकरीबन 10 प्रतिशत है। इसके तहत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को गति देने की कोशिश की गई है। जिनमें कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः अभी की सबसे बड़ी जरूरत है कि धन का प्रवाह तेजी से नीचे की ओर जाए और बड़ी जनसंख्या की आर्थिक हैसियत बढ़े। इसके लिए सरकार ने 'मनरेगा' में 40 हजार करोड़ रूपये के अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था की है, जो निश्चित ही नकद को नीचे तक पहुँचाएगा और सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा।

इसी प्रकार कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों को राहत देने की कोशिश की गई जिसमें 'एसेंसियल कमोडिटी एक्ट-1955' में आवश्यक सुधार महत्वपूर्ण हैं। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में 2 लाख करोड़ रूपये जारी किये गए हैं, इससे किसानों की क्रय क्षमता बढ़ेगी। इसी प्रकार कृषि के बाद रोजगार के दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र 'एमएसएमई' सेक्टर के लिए आपात क्रेडिट सुविधा के रूप में 3 लाख करोड़ रूपये जारी किये गए तथा उन्हें कोलेट्रल फ्री लोन की व्यवस्था की गई। इससे यह क्षेत्र न केवल कामगारों को वेतन दे सकेगा। बल्कि इससे उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद भी संभव हो सकेगी। राज्य सरकारों की आर्थिक हैसियत बढ़ाने के लिए वित्तीयन पूर्ति की सीमा को 6.41 लाख करोड़ रूपये से बढ़ाकर 10.69 लाख करोड़ रूपये कर दिया गया है। कुल मिलाकर इसके तहत हर क्षेत्र को इतनी आर्थिक सहायता दी गई है कि वो वापस अपनी गति में आ सके। इस प्रकार तीनों मोर्चों पर देखें तो भारत सरकार काफी सक्रिय, चपल और संतुलित दिखती है। सरकार के इन महत्वपूर्ण कदमों के आधार पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश इस कोरोना संकट से उबरने में जल्द ही सफल होगा।

(लेखक इतिहास के अध्येता हैं तथा विभिन्न अखबारों तथा ऑनलाइन पोर्टल के लिए लिखते हैं, इस लेख में उनके विचार निजी हैं)

बस प्रकरण : लोगों की 'सेवा' का दावा कर रही कांग्रेस की मंशा पर उठते हैं गहरे सवाल

अनुराग सिंह

भारतीय राजनीति में एक समय तक चुनावी वादों को महज छलावा समझा जाता रहा है। आजादी के बाद जो राजनीतिक रवायत चली उसमें पार्टियाँ लगातार चुनाव के समय वादें करती और बाद में उन्हीं को अगले चुनावों में भी इस्तेमाल किया जाता। इस तरह यह एक सामान्य प्रक्रिया बन गयी और चुनावी वादे महज छलावा। हमने इंदिरा गांधी का दौर देखा कि किस तरह भारत में 'गरीबी हटाओ' के नारे दिए गए लेकिन उसके बाद भी उन्हीं की पार्टी की कई बार सरकारें रहीं मगर देश में गरीबों की स्थिति और गरीबी यथावत बनी रही।

कुल मिलाकर जो बात कहनी थी वह यह है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा कही गयी बातों की कोई जवाबदेही नहीं रहती थी लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन के बाद से अब इस आदत को भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बदलने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी की यह आदत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मौजूदा संकट के समय में प्रियंका गांधी के एक हज़ार बसों से मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की बातों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है।

कोरोना के इस भीषण समय में बड़े-बड़े महानगरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर श्रमिकों का पलायन बड़ी मात्रा में जारी है। ऐसी स्थिति में मजदूरों के दर्द साझा करने के क्रम में, उनको सहूलियत देने की बात प्रियंका गांधी ने कही और ऐलान किया कि वे उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक हज़ार बसें मुहैया कराएंगी जिससे उन मजदूरों को उनके घर पहुँचाया जाएगा।

असल में मजदूरों के नाम पर राजनीति यहीं से शुरू हुई। उनके इस बयान के बाद पूरी मीडिया में यह खबर फ़ैल गयी। जैसा पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि कुछ भी कह देने की आदत और उसके बाद उस बात पर

जवाबदेही न होना यहां की राजनीतिक आदत में शमिल है। हो सकता है प्रियंका गांधी का यह दांव ऐसा ही रहा हो।

चूंकि प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया, ताकि इससे बात यह सामने आए कि सरकार और सत्ता में न रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हितों का ख़याल कर रही है, जब सत्ताएं मजदूरों को साधन मुहैया नहीं करा पा रही हैं। इस तरह कांग्रेस पार्टी मसीहा बन कर सामने आती। उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर चुप्पी साध लेगी, बैकफुट पर आ जायेगी और इसी बहाने इनकी राजनीति सफल रहेगी।

प्रियंका गांधी का आरोप था कि हम एक हज़ार बसों के साथ तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तुरंत पत्र लिखकर यह कहा गया कि हम इसके लिए तैयार हैं। आप हमें उन एक हज़ार बसों के विवरण, उनके फिट होने का प्रमाण, उनके चालकों का विवरण मुहैया कराएँ, ताकि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें।

यह कहने की देर थी कि प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी में एक तरह की हलचल देखने को मिली कि शायद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे उत्तर और सहयोग की उम्मीद नहीं थी। अब जवाबदेही का समय प्रियंका गांधी का था, जिन पर जल्द से जल्द एक हज़ार फिट बसों को उनके चालकों के साथ मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी थी। जब उत्तर प्रदेश सरकार को एक हज़ार बसों की लिस्ट सौंपी गयी तो कुछ अलग ही तथ्य उजागर हुए।

शायद प्रियंका गांधी की परिभाषा के अनुसार चार पहिए का एम्बुलेंस, चार पहिए वाली कार, तीन पहिए वाला ऑटो रिक्शा, सामान ढोने वाली गाड़ियों को बस कहा जाता है इसलिए उनके द्वारा दी गयी एक हज़ार बसों की सूची में ये वाहन भी शामिल पाए गए। आरटीओ विभाग के द्वारा लखनऊ पुलिस कमिशनर को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक़ कांग्रेस द्वारा मुहैया कराई गयी 1049 वाहनों की सूची में 879 ही बसें हैं, जबकि बाकी वाहन ट्रक, ऑटो, एम्बुलेंस आदि हैं। इससे जाहिर है कि बिना वाहनों के समुचित प्रबंध के ही प्रियंका गांधी घोषणा करती घूम रही थीं। क्या इसे मजदूरों के नाम पर होने वाली राजनीति न कहा जाए?

एक तरफ राहुल गांधी यह बयान देते हैं कि यह महामारी का समय राजनीति भूल कर एक साथ काम करने का है, लेकिन फिर यह क्या है? क्या राहुल गांधी का वह बयान भी महज़ राजनीति से प्रेरित था? कांग्रेस पार्टी को इसका मुकम्मल जवाब देना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात एक हज़ार बसों के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी की मंशा पर है। जिन बसों की कतारें मीडिया दिखा रही है जो कथित रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा मजदूरों को घर भेजने के लिए खड़ी हैं, उनमें राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग की बसें भी शामिल हैं। यदि आपको यह कार्य करना था तो राजस्थान से जो बसें

यहाँ कतारबद्ध की गयीं थी, उनमें राजस्थान से श्रमिकों को क्यों लेकर नहीं आया गया?

यदि ऐसी पहल पहले उन्होंने की होती तो जिन मजदूरों की जान राजस्थान से आने के क्रम में हुई शायद वह दुर्घटना न हुई होती। यदि आपको सच में यह करना था तो मुंबई में लाखों की संख्या में मजदूर फँसे हुए हैं, वहां पर आपकी ही पार्टी की मिली जुली सरकार है, वहां यह पहल क्यों नहीं की गयी?क्या वहां एक बार भी इस बारे में चर्चा भी करना ज़रुरी समझा गया? जबकि मुंबई में आज फिर झूठी ट्रेन के अफवाह पर पांच हज़ार से अधिक श्रमिक रेलवे स्टेशन पर जुट गए।

यदि वास्तव में प्रियंका गांधी को मजदूरों के हित के लिए कार्य करना था तो उन्हें बहस को उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं करना चाहिए था, अपितु उससे पूर्व महाराष्ट्र में जितने पूर्वांचल के श्रमिक अपने घर-गाँव वापस लौटने के लिए छटपटा रहे थे, उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए था।

समग्रतः देखने-सुनने में तो यह एक शानदार पहल लगती है, लेकिन इस विषय पर ठहर कर सोचने के बाद यह प्रियंका गांधी के द्वारा उनकी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार से पटी सियासत की विरासत को आगे बढ़ाने और मजदूरों के नाम पर रोटी सेंकने के छल के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रतीत होता।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। पत्र-पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन करते हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

'सशक्त नारी, समर्थ समाज' के पथ पर अग्रसर योगी सरकार

खुशबू गुप्ता

वर्तमान में कोरोना महामारी ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट के साथ-साथ सम्पूर्ण मानवता के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। इसने न केवल गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता को जन्म दिया है बल्कि सरकारों को आधारभूत संरचनात्मक ढांचे में व्यापक सुधार और परिवर्तन करने पर भी विवश किया है।

सरकारें समय की आवश्यकता को केंद्र में रखकर नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक नियोजन पर बल भी दे रही हैं। जहाँ सरकार के समक्ष इस वैश्विक महामारी ने चुनौती उत्पन्न की है, वहीं सरकारें इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का कार्य भी कर रही हैं।

गौरतलब है कि समाज के विकास की प्रक्रिया में देश की आधी आबादी की महती भूमिका होती है। नारी की महत्ता को केंद्र में रखकर उन्हें सशक्त बनाने हेतु लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कानून, विकासात्मक नीतियों का निर्माण, विभिन्न योजनायें, कार्यक्रम जैसी पहले की जाती रही हैं। इसी सन्दर्भ में यदि हम वर्तमान संकट के समय महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार की योजनाओं, नीतिओं, कार्यक्रमों की बात करे तो केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।

आज महिलाएं कोरोना की नई योद्धा के रूप में अपना योगदान कर रही हैं। जहाँ एक तरफ महामारी से प्रवासी श्रमिक तथा स्थानीय क्षेत्रों के लोग बहुत व्यापक रूप से बेरोजगारी, गरीबी के शिकार हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो योगी सरकार ने इस गंभीर समस्या को अवसर के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है।

स्वावलंबी और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए योगी सरकार द्वारा एमएसएमई तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में नीतियों में संशोधन के लिए कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से "हर हाथ को काम हर घर को रोजगार" के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिए यूपी सरकार दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है।

"बैंकिंग कॉरसपोंडेंट सखी योजना" के तहत 58000 स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी। इस योजना से ग्रामीण महिलाएं बैंकों से जुड़कर नकदी का लेनदेन घर-घर जाकर करवाएंगी। योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों का निकासी और जमा डिजिटल रूप से होगा, खाता धारकों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

महिलाओं को "स्किलमैपिंग" के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसी सन्दर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, "प्रत्येक महिला में उद्यमिता के गुण और मूल्य होते हैं। यदि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों तो महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं"

"मास्कअप इंडिया" मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों (सेल्फहेल्पग्रुप्स)के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। हाल ही के आकड़ों को देखे तो प्रदेश में पर्सनल प्रोएक्टिव इक्विपमेंट एवं मास्क सहित कुल लगभग 70 इकाइयाँ क्रियाशील हैं। वर्तमान में जब देश के भीतर मास्क की मांग बढ़ी है, तब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं मास्क की आपूर्ति संपूर्ण देश में कर रही हैं।

उल्लेखनीय होगा कि महिलाओं को प्रदेश सरकार न केवल रोजगार उपलब्ध करा रही बल्कि उनके उत्पादों की मार्केटिग एवं ब्रांडिंग भी करा रही है। इस सन्दर्भ में जिक्र जरूरी होगा कि दिल्ली और बुलंदशहर में 3000 से भी अधिक स्थानीय ग्रामीण महिलाएं मास्क बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। बुलंदशहर स्थानीय प्रशासन के द्वारा डिजाइनरमास्क का निर्माण कर सम्पूर्ण देश में भेजा जा रहा है तथा छः महीने में लगभग 50000 महिलाओं को जोड़कर उनको रोजगार उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है।

"मास्कअप इंडिया मिशन" के तहत कई गैर सरकारी संस्थाओं ने भी मुहिम छेड़ रखी है जिसके विषय में 25 जून, 2020 को प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्वीटर से यह भी बताया गया कि रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनती स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 50 हज़ार की पूंजी से 30 लाख कमाए जो कि बहुत ही सराहनीय है।

बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के "स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण" की दिशा में कार्य करते हुए यह भी निर्देश दिया गया कि मास्क का उपयोग न करने पर जिस व्यक्ति का चालान हो उसे ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित मास्क उपलब्ध कराया जाए।

महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कई घोषणाएं भी की गयी हैं। उदाहरणस्वरूप 86 लाख वृद्धावस्था, दिव्यांगजन तथा निराश्रित महिला लाभार्थियों को दो माह की पेंशन का भुगतान एक साथ किया गया है। 4 जून 2020 तक के आकड़ों के अनुसार निराश्रित महिला पेंशन धारकों के अकाउंट में 1500 की

धनराशि तथा 130.31 मासिक पेंशन तथा "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" पैकेज के तहत 260.62 करोड़ की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की गई।

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा "उज्जवला योजना" के लगभग 1.47 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराये गए हैं। बता दें कि प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य भी है। "मुद्रा योजना" और "स्टैंडअप इंडिया" के तहत प्रदेश सरकार महिला लाभार्थियों को उद्योगों के लिए आर्थिक ऋण प्रदान कर रही है।

साथ ही साथ, निराश्रित महिला पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जा चुका है। किशोरियों में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से पहले से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लाई गयी, सामूहिक विवाह के लिए सहायता धनराशि बढ़ाकर 51000 कर दिया गया, पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी के लिए "पोषण पखवाड़ों" का आयोजन करने जैसे काम किए गए हैं।

वर्तमान में, 12 जून को प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई कि "बाल श्रमिक विद्या योजना" के तहत बालिकाओं को 1200 की धनराशि प्रतिमाह तथा साथ ही साथ कक्षा 8, 9, 10 उत्तीर्ण करने पर प्रतिवर्ष 6000 की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। बच्चों को बालश्रम से अलग कर शिक्षा से जोड़ने हेतु योजना लागू करने वाला यूपी देश का प्रथम राज्य बन गया है।

प्रदेश सरकार उनकी प्रतिभा के अनुरूप उन्नति के अवसर उपलब्ध करने के लिए संकल्पित है। देश में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए "मिशन अनिवार्य" की शुरुआत की गयी है, जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त में सैनेटरीपैड का वितरण भी किया जा रहा। दिल्ली एन.सी.आर से लेकर देश के अन्य जगहों पर सैनेटरीपैड के वितरण का कार्य भी सराहनीय है।

इसके अलावा लिखना आवश्यक होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाओं, सहायता और जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध नजर आई है। झाँसी की महिला पुलिस मास्क बना रहीं, वहीं उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश बॉर्डर पर "पैडमैन" की तरह प्रवासी महिलाओं को निःशुल्कसैनेटरीपैड के वितरण के कार्य द्वारा भी झाँसी खासा चर्चा में रहा है।

सभी प्रवासी श्रमिको को रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दिशा में प्रदेश सरकार तथा इडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नारडेको के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के 11 लाख श्रमिकों/कामगारों को रोजगार प्राप्त होगा जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।

इससे स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को गति मिलेगी साथ ही साथ व्यापक स्तर पर लोगो को रोजगार भी प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अब महिलाओं के कल्याण के साथ-साथ उनके नेतृत्व के विकास का भी है। योगी सरकार राज्य, जिला, ग्रामीण स्तर पर विद्यमान संस्थागत तंत्रों को मजबूती प्रदान करते हुए महिलाओं को सशक्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन, जरूरी प्रशिक्षण तथा समर्थनीय कौशल को सुनिश्चित कर रही है।

नए भारत के निर्माण की तरफ अग्रसर होते हुए देश की आधी आबादी की विकास प्रक्रिया में भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए इसी सन्दर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने विगत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा था, "सशक्त महिलाओं का मतलब है कि महिलाओं को अपने व्यक्तिगत लाभों के साथ ही साथ ही समाज के लिए अपने स्वयं के निर्णय ले सकने में सक्षम हो"।

इसकी प्रासंगिकता को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यह कहना उचित होगा कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी नए भारत के निर्माण को आधार प्रदान करती है। आवश्यकता है सकारात्मक सोच की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले परिवेश की, नीतियों का क्रियान्वयन कर महिलाओं के समावेशन की, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, समान कार्य के लिए समान वेतन की और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर विकास प्रक्रिया में उनको शामिल करने की, जिससे वे अपने कौशल, अपनी क्षमता को मूर्त रूप प्रदान कर सकें।

(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना संकट के दौर में यूपी सरकार ने जीता जनता का दिल, मुद्दाविहीन हुआ विपक्ष

▸ प्रणति तिवारी मुखर्जी

कोरोना संकट से निपटने में यूपी के मुख्यतमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस कुशल प्रबंधन के साथ प्रदेश का नेतृत्व किया, न केवल प्रदेश अपितु देश की जनता भी उसकी कायल हो रही है। यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि कई विकसित देशों की तुलना में योगी सरकार ने अपने प्रदेश के करोड़ो निवासियों को इस महामारी से बचा लिया है और अब दुनियाभर में योगी की इन नीतियों को सबक के तौर पर देखा जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन चुके योगी आदित्य नाथ के प्रबंधन की सराहना विपक्ष भले न कर पा रहा हो, लेकिन यह तय है कि कोरोना के इस दौर में योगी के कामकाज ने विपक्ष के लिए सवाल उठाने के नामपर कुछ भी नहीं छोड़ा है। हालत यह है कि पार्टियां राजनीति के नाम पर रोजाना सिर्फ ट्वीटर पर ट्वीट कर ले रही हैं। यह कहना अतिश्योटक्ति नहीं होगी कि इन दिनों मुद्दों के अभाव में विपक्ष की कमर टूट चुकी है।

महामारी जैसे प्राकृतिक संकट से निपटना एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के लिए यह वह मौका था जिसमें निःसंदेह वे अपने लिए राजनीतिक अवसरों की उम्मीद लगाए होंगे। विपक्ष की सोच रही होगी कि जब योगी सरकार महामारी के जाल में फंस जाएगी और अव्यवस्था से सबकुछ तहस-नहस होने लगेगा तो वे सरकार की आलोचना कर अपनी राजनीति चमकाएंगे। लेकिन जिस प्रकार योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरी शक्ति लगाकर काम किया और प्रबंधन को दुरुस्त रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग तक की, वह अविस्मरणीय है।

पिछले छः साल से विपक्ष सरकार के सामने कई चुनौतियों को सजा चुका है और योगी उन तमाम चुनौतियों के मामले में अपने शानदार प्रबंधन की बदौलत दुनिया के सामने अपने कौशल का उदाहरण पेश करते दिखते रहे हैं। ऐसे में जब इस वैश्विक महामारी ने देश में प्रवेश किया तो विपक्ष चुप्पी साधे तमाशा देखता रहा।

पार्टियों को यह पता था कि जिस समस्या का समाधान अमेरिका, यूरोप और अन्य देश नहीं निकाल पाए, उस समस्या से बीजेपी की योगी सरकार किस आधार पर इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश को बचा पाएगी। लेकिन योगी सरकार ने हर बार की तरह चुनौतियों का जवाब अपने कुशल अनुशासित प्रबंधन से दिया।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए सारी अनुकूल संभावनाएं मौजूद थीं। वहीं पड़ोसी राज्ये तेजी से फैलती महामारी के सामने हथियार डालते दिख रहे थे। आरोप-प्रत्यातरोप का दौर शुरू था। केंद्र के कठोर कदमों पर सवाल किए जा रहे थे। वहीं खुद की असफलता का बोझ केंद्र सरकार पर मढ़ने का प्रयास भी जारी था।

उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली, मुंबई, गुजरात और कई संक्रमित प्रदेशों से लौट रहे बिहार और यूपी के करीब 30 लाख कामगारों को सुरक्षित स्थानांतरित करने के प्रयास में जुटी थी। मीडिया में लगातार नकारात्मक खबरों का सिलसिला जारी था।

लेकिन इन सबके बावजूद योगी सरकार के जज़्बे में कोई कमी देखने को नहीं मिली। नकारात्मक माहौल के बावजूद योगी ने चौबीस घंटे अपनी निगरानी में एक हजार बसें गाजियाबाद बॉर्डर पर भेजीं और हजारों किलोमीटर चल कर सफर कर रहे श्रमिकों को उनके गांवों तक पहुंचाया।

इस दौरान कोटा में फंसे छात्र-छात्राओं को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। महाराष्ट्र समेत सभी प्रदेशों ने यूपी के श्रमिकों को राशन देना बंद कर दिया। तमाम तरह की मजबूरियों के बावजूद एक जिम्मेदार अभिभावक के तौर पर योगी ने इनकी समस्याओं को समझा और जिम्मादारी अपने सिर पर ली। केंद्र सरकार से तुरंत बात की और छात्रों को लाने की व्यवस्था की। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाई गईं और लाखों प्रवासी श्रमिकों को उनके परिवार के पास लौटने की व्यवस्था की गयी।

इन सबके बीच संक्रमण के इस दौर में स्वास्थ्य परीक्षण योगी सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकता थी। जरूरत के हिसाब से मुफ्त इलाज भी दिया गया। जरूरतमंदों के खातों में नकद राशि डाली गई और माहौल सामान्य होने पर सबको रोजगार भी मुहैया कराया गया। आइसोलेशन सेंटर से लेकर बाजार और रिहाइशी इलाकों को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया।

सरकार के इन प्रयासों को जनता ने भी सिर आंखों पर लिया और अनुशासन का पालन करती दिखी। हालांकि कोरोना के साथ जंग अभी जारी है, फिर भी सरकार के हौसले के सामने यह महामारी कई मायनों में नियंत्रित दिख रही है। वहीं अब यूपी में विपक्षी पार्टियों के हालात भी कोरोना के हालात जैसे ही दिख रहे हैं। पार्टियां नियंत्रण में हैं, शांत हैं।

उधर संक्रमण काल के दौरान योगी के इन ऐतिहासिक प्रयासों को जनता सराह रही है। वर्षों से मौजूद जातिवाद टूटता नजर आ रहा है। प्रदेश के लोग सरकारी व्यवस्था से खुश हैं। प्रदेश का किसान खुश है, मेहनतकश खुश हैं।

हालांकि योगी के पास गिनाने के लिए तमाम उपलब्धियां मौजूद हैं, लेकिन इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि राज्य की जनता एकजुट हो रही है, उनके बीच भेदभाव टूट रहा है, वंचितों को सुविधाएं मिल रहीं हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो रही और करोड़ो परिवार अपने घरों के पास रोजगार हासिल कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त बिजली पानी की परियोजनाएं कई गुना गति से आगे बढ़ रही हैं। इन सब के बीच विपक्षी पार्टियां हो न हों अपने भाग्य का इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब समाज में कुछ संवेदनशील मुद्दे उठें और जातियां टूटें, धर्म टूटे। लेकिन देश की आम जनता योगी और मोदी की निष्ठा को परख चुकी है। ऐसे में पार्टियों को अब राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विकास की एक और लंबी रेखा खींचनी होगी।

आलोचना के साथ-साथ जनहित के सही कार्यों के लिए सरकार की सराहना भी करनी होगी। नकारात्मक राजनीति से परहेज करना होगा और जनसेवा के लिए सरकार के समक्ष नए पायदान हासिल करने होंगे। हालांकि अभी के हालात में विपक्ष के लिए ये सब आसान नहीं नजर आता। अभी तो देश-प्रदेश की जनता में बस मोदी और योगी का ही नाम गूँज रहा है।

लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।

कोरोना संक्रमण के आगे दिल्ली-सरकार ने टेके घुटने, अमित शाह ने थामी कमान

नेशनलिस्ट टीम

दिल्ली सरकार राजधानी में फैले कोरोना संक्रमण के सामने घुटने टेक चुकी है। हालात हाथ से बाहर जाते देख अब देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राजधानी की कमान अपने हाथों में ले ली है। दिल्ली के लोगों को कोरोना से राहत दिलाने के पहले प्रयास के रूप में सबसे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई।

बैठक में यह मांग की जा रही थी कि कोरोनाटेस्ट की कीमतें बहुत ही ज्योदा हैं जिसे आधा किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए अमित शाह ने तुरंत ही इसे मंजूरी दे दी। इस तरह राजधानी वालों के लिए ये कोरोना से संबंधित यह एक राहत भरी बात रही और अब दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग की कीमत आधी हो जाएगी।

सर्वदलीय बैठक के बाद कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शाह ने कई अहम फैसले लिए। एक फैसला यह हुआ कि 20 जून से दिल्ली सरकार रोजाना कोरोना के 18000 टेस्ट करेगी। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि राजधानी दिल्लीी की गंभीर हालत को देखते हुए दो दिनों में कोरोना संक्रमण की जांच दोगुनी की जाए तथा छह दिन बाद इसे तीन गुना तक तक बढ़ा दिया जाएगा।

इससे बीमारी को पहचानने में मदद तो मिलेगी ही, लोगों को सही इलाज समय पर मुहैया कराया जा सकेगा। यही नहीं, यदि टेस्टिंग ज्यादा हुई तो राजधानी में कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने में भी तेजी आएगी।

ये तो हुई कोरोना संक्रमण के टेस्टिंग की बात। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए और उसके चार्ज किए जाएं। इस मामले को भी संज्ञान में लेते हुए गृहमंत्री ने एक समिति गठित की है जो 2 दिनों के भीतर इस मामले पर सही जानकारी देती एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट के

आधार पर निजी अस्पतालों के बेड और अन्य तमाम सर्विस चार्जों की प्राइसकैपिंग की जाएगी।

राजधानी में बढ़ते मरीजों की तादाद और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली को 500 रेलवे आइसोलेशन कोच उपलब्ध होंगे, जिससे 8,000 अतिरिक्त बेड की जरूरत पूरी की जा सकेगी। यही नहीं, यहां घर-घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगी।

इसके अलावा अच्छे से निगरानी हो, इसके लिए वहां हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करवाया जाएगा। साथ ही, महामारी से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार के लिये भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे।

महामारी के सामने असफल होती दिल्ली- सरकार की मदद के लिए अब केंद्र ने अपने पांच सीनियर अधिकारी भी दिल्ली सरकार को दिए हैं। यह अधिकारी दिल्ली सरकार को ना सिर्फ कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में सही निर्णय लेने तथा प्लानिंग पर काम करेंगे बल्कि महामारी के मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

इस सर्वदलीय बैठक में शाह ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग, एम्स और दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चिकित्सकों का एक संयुक्त दल राजधानी के कोविड समर्पित अस्पतालों का दौरा कर वहां स्वास्थ्य व्यवस्था व तैयारियों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

बता दें कि भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे ऑक्सीजनसिलेंडर, वेंटिलेटर, पल्सऑक्सीमीटर व अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने को लेकर भी आश्वस्त किया है।

गौरतलब हो कि दिल्ली में अभी तक कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 39,000 के करीब पहुंच गई है और 1,200 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। यही नहीं, दिल्ली अब महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद देश में तीसरा सबसे अधिक कोरोनावायरस से संक्रमित राज्य बन गया है।

केंद्र सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही कोरोना का सामना करने के लिए पूरे देश को किया एकजुट

ए. सूर्यप्रकाश

कोविड-19 महामारी के संकट में भले ही यहां-वहां कुछ बेसुरे राग सुनाई पड़े हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीयों ने अनुशासन और एकजुटता के साथ इस आपदा का सामना किया है। इस गाढ़े वक्त में जिस किस्म का नियोजन और आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा वह हमारे विविधता भरे और बहस प्रिय समाज में दुर्लभ ही दिखता है। कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन का सामना करने के लिए एक संयुक्त कमान बनाने की प्रतिबद्धता ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य स्तर के सभी संस्थानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वास्थ्यकर्मियों को एकजुट कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अग्रिम मोर्चे से कमान संभाले हुए हैं। हालांकि कहने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ ठीक-ठाक है।

कोरोना पर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों का केंद्र के साथ तालमेल सही नहीं

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से कुछ ऐसे स्वर उभरे जिनसे लगा कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का केंद्र के साथ तालमेल सही नहीं। स्थिति को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार ऑनलाइन बैठकें कर उनकी समस्याएं समझने का प्रयास किया। यह उस सहकारी संघवाद की भावना को ही रेखांकित करता है जिसकी यदाकदा चर्चा होती रहती है।

किसी संकट से निपटने के मामले में संविधान केंद्र सरकार को विशेष अधिकार प्रदान करता है

यह बात अवश्य याद रखी जानी चाहिए कि किसी संकट से निपटने के मामले में एकरूपता कायम रखने के लिए संविधान केंद्र सरकार को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई। हालांकि इन अधिकारों पर बहुत बहस भी हुई। संविधान शिल्पी डॉ. बीआर आंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था कि संविधान को लेकर ऐसे आरोप हैं कि

इसमें केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां देकर राज्यों को महज म्युनिसिपैलिटी की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन यह न केवल अतिरेकपूर्ण है, बल्कि संविधान के लक्ष्यों को लेकर नासमझी को भी दर्शाता है।

आंबेडकर ने कहा था- केंद्र विशेष अधिकार का प्रयोग केवल आपातकाल में ही कर सकता है

एक और आरोप यह था कि केंद्र को शक्ति इसलिए दी गई कि वह राज्यों पर अपने फैसले थोप सकता है। इस आरोप की चर्चा करते हुए आंबेडकर ने समझाया था कि यह संविधान का सामान्य प्रावधान नहीं है और इसका उपयोग केवल आपातकाल में हो सकता है। यह कहते हुए उनके दिमाग में केवल आपातकाल की उद्घोषणा को लेकर संविधान में शामिल अनुच्छेद ही नहीं थे, बल्कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची एवं समवर्ती सूची में आपातस्थिति को लेकर केंद्र द्वारा कानून बनाने की शक्तियों का भी भान था।

समवर्ती सूची- केंद्र विषाणुओं की रोकथाम के लिए कानून बना सकता है

जैसे कि समवर्ती सूची में आइटम 23 केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में संक्रमण रोकने या मनुष्य, पशु और वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले विषाणुओं की रोकथाम के लिए कानून बना सकता है। मौजूदा कोरोना संकट में आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।

आपदा प्रबंधन एक्ट महामारी के दौरान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र को अधिकार प्रदान करता है

आपदा प्रबंधन अधिनियम महामारी के दौरान राष्ट्रीय नीति बनाने एवं उनके समन्वय के लिए केंद्र को अधिकार प्रदान करता है। इसके तमाम प्रावधान किसी राष्ट्रीय आपदा के समय केंद्र को ऐसी शक्तियां देते हैं। इन्हीं के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन और फिर अनलॉक से संबंधित आदेश जारी किए। ऐसे ही एक आदेश में प्रवासी मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन को देखते दुए शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सौंपी गई। इसमें जिला अधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षकों को लॉकडाउन से जुड़े नियमों को लागू कराने के लिए जवाबदेह बनाया गया। यह इसलिए किया गया, क्योंकि डीएम और एसपी अमूमन केंद्रीय सेवाओं से आते हैं और वे इससे भलीभांति परिचित होते हैं कि इन नियमों को न मानने के क्या नतीजे हो सकते हैं? डीएमए के अलावा एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1987 भी किसी महामारी के नियंत्रण में केंद्र को शक्तियां प्रदान करता है।

केंद्र ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों की पड़ताल के लिए टीम भेजी थी

हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना के लिहाज से संवेदनशील कुछ जिलों की पड़ताल के लिए केंद्र द्वारा भेजी गई टीमों पर आपत्ति जताई और कुछ अन्य दलों ने भी इससे सुर मिलाते हुए केंद्र के खिलाफ तान छेड़ी, लेकिन केंद्र ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही ये कदम उठाए, जिसकी बुनियाद सात दशक पहले डॉ. आंबेडकर और उनके साथियों ने रखी थी। संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और वह आपातकाल में राज्यों पर भी अपने निर्णय बाध्यकारी बना सकता है। यह केंद्र को अर्ध संघीय सरकार जैसे तंत्र के रूप में पेश करता है। वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञ केसी वाघमारे के अनुसार भारत संघीय चरित्र वाला केंद्रीय राज्य है न कि केंद्रीय चरित्र वाला संघीय राज्य।

आपात स्थिति में नागरिकों की अवशिष्ट निष्ठा राज्यों के बजाय केंद्र में होनी चाहिए- आंबेडकर

अपने समापन भाषण में कतिपय आपात स्थितियों में शक्तिशाली केंद्र को लेकर डॉ. आंबेडकर ने कुछ दलीलें भी पेश की थीं। उन्होंने कहा था कि अधिकांश लोगों का यह मानना है कि किसी आपात स्थिति में नागरिकों की अवशिष्ट निष्ठा राज्यों के बजाय केंद्र में होनी चाहिए। देश के समग्र और साझा हितों में केंद्र ही काम कर सकता है। आपात स्थिति में राज्यों की तुलना में केंद्र को वरीय शक्तियां देने का यही आधार है। इसमें राज्यों के लिए भी ताकीद है कि आपातकाल में राज्यों को समग्र राष्ट्र हितों और धारणाओं पर गौर कर अपने स्थानीय हितों पर भी विचार करना चाहिए। जो समस्या को नहीं समझेंगे, केवल वही इसे लेकर शिकायत कर सकते हैं।

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत केंद्रीय शक्ति ही निपटने में मददगार हो सकती है

डॉ. आंबेडकर अपने देश और उसकी जनता को भलीभांति समझते थे और उन्हें अनुमान था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिलहाल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शासन-संचालन से 42 विभिन्न दल जुड़े हुए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में कुछ के प्रयास विपरीत दिशाओं में जाते प्रतीत हो रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच पर्याप्त परामर्श के साथ एक मजबूत केंद्रीय शक्ति ही इस समस्या से निपटने में मददगार हो सकती है।

महामारी और आपातकाल से निपटने के लिए हमें एक सशक्त संवैधानिक ढांचा मिला

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की वार्ता से ऐसा किया भी है। हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस महामारी और राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए हमें एक सशक्त संवैधानिक ढांचा प्रदान किया

(यह लेख दैनिक जागरण से लिया गया है, लेखक प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन हैं)

कोरोना संकट से निपटने में CM योगी के कौशल की सराहना PM से लेकर पाकिस्तान तक कर रहे

सद्गुरु शरण

उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के लिए अच्छे दिन फिलहाल आते नहीं दिखते। बगैर लाग-लपेट कहा जाए तो 2014 से बार-बार पटखनी खा रहे विपक्षी दलों को अपने ही बिछाए उस जाल से बाहर निकलने की तरकीब नहीं सूझ रही जिसमें वह भाजपा को फंसाना चाहते थे। इन दलों के लिए सबसे बड़ी निराशा यह है कि कोरोना से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली।

इन्हें उम्मीद रही होगी कि कोरोना से निपटने में योगी सरकार कामयाब नहीं होगी, पर प्रदेश का सौभाग्य और विपक्षी दलों का दुर्भाग्य कि कोरोना संकट से निपटने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कौशल एवं प्रबंधन की सराहना प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान तक कर रहे हैं।

जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के भारत सहित सिर्फ पांच देशों से छोटे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए सारी अनुकूलताएं मौजूद थीं। उस पर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, नासिक, सूरत और कई अन्य सघन संक्रमित प्रदेशों से लौटे करीब 30 लाख कामगारों ने कोढ़ में खाज जैसे हालात पैदा करने की जमीन तैयार कर दी थी। दिल्ली वाली दीदी और लखनऊ वाले भतीजे ने कटाक्षपूर्ण ट्वीट शुरू भी कर दिए थे, पर योगी आदित्यनाथ ने हथियार नहीं डाले। जब यूपी के कई लाख कामगार अंधेरे में दिल्ली से खदेड़े गए, तब योगी ने रात भर जागकर एक हजार बसें गाजियाबाद बॉर्डर भेजीं और सभी श्रमिकों को उनके घर भिजवाया।

जब राजस्थान सरकार ने कोटा से यूपी के विद्यार्थियों को शहर से जाने का अल्टीमेटम दे दिया, तब योगी ने बसें भेजकर सारे बच्चों को उनके घर भिजवाया। जब महाराष्ट्र समेत सभी प्रदेशों में यूपी के श्रमिकों को राशन देना बंद कर दिया, तब योगी ने केंद्र सरकार से बात करके श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाईं और लाखों प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंच सके। सभी आगंतुकों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। जिन्हें जरूरत थी, उन्हें इलाज मुहैया कराया गया। खातों में नकद राशि डाली गई और माहौल सामान्य होने पर सबको काम पर लगाया गया। कोरोना अब भी मौजूद हैं, पर उसका हौसला पस्त हो रहा है। उसके साथ विपक्षी दल भी पस्त हो रहे हैं।

पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने लिखा कि कोरोना से कैसे लड़ा है, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। योगी के लिए इससे बड़ी और संतोषदायक सराहना क्या हो सकती है, पर विपक्ष अब क्या करे? धान-गेहूं खरीद की सरकारी व्यवस्था से किसान खुश हैं। योगी के पास गिनाने को तमाम अन्य उपलब्धियां हैं, पर मौजूदा केंद्र-राज्य सरकार के शासनकाल में यूपी में एक बड़ा बदलाव आया। वो है, जातिवाद का बहुत कमजोर पड़ जाना। इसका श्रेय सरकार की नीतियों और कार्यशैली को जाता है।

दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर जाति के गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुईं, यूपी के विपक्षी दल उनका मर्म भांप नहीं पाए। जिन वंचित परिवारों में पहली बार एलपीजी सिलिंडर और चमचमाता स्टील चूल्हा पहुंचा, जिनके हाथों में पहली बार पासबुक पहुंची और जिन गरीबों के खातों में पहली बार सीधे नकद पैसा पहुंचा, वे प्रधानमंत्री के मुरीद हो गए। इसका असर 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव में साफ दिखा, पर विपक्ष की आंखों पर चढ़ा मोतियाबिंद उसे साफ नहीं देखने देता।

जातियों के वोटबैंक दरक चुके हैं, पर विपक्ष यह सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं। इन दलों को आज भी उम्मीद है कि मुसलमान भाजपा को विरोध ही करेंगे। उन्हें शायद पता नहीं कि कोरोना काल और इससे पहले करोड़ो मुस्लिम परिवारों को सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है। इसके बावजूद विपक्ष को उम्मीद है कि यूपी में उसकी किस्मत से कोई चमत्कार होगा। धर्म और जातियों के नाम पर विभाजक रेखाएं खिंच जाएंगी। कुछ लोग भाजपा का समर्थन करेंगे, जबकि बाकी लोग मजबूरी में विपक्ष का साथ देंगे। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। रोज दो-चार ट्वीट करते रहो। बस हो गई राजनीति। विपक्ष यह नहीं समझ पा रहा कि मोदी-योगी की जोड़ी ने राजनीति को कितना पेशेवर, जवाबदेह और सकारात्मक बना दिया है।

लोगों को विश्वास है कि नतीजा कुछ भी रहे, पर मोदी-योगी की मंशा में ईमानदारी है। राजनीति का यह ऐसा फॉर्मेट है, जहां विपक्ष को आरोप-प्रत्यारोप की नकारात्मकता से बाहर निकलकर सार्थक योगदान करना होगा। मोदी-योगी की लकीर मिटाने की आदत त्यागकर उसके समानांतर बड़ी लकीर खींचनी होगी। आम आदमी परफॉर्मेंस देखना चाहता है। विपक्ष को अवसर पर नजर रखनी चाहिए, यद्यपि मोदी-योगी के सामने अवसर मिलना आसान नहीं

(यह लेख दैनिक जागरण से लिया गया है, लेखक दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के स्थानीय सम्पादक हैं.)

आत्मनिर्भरता की बुनियाद

जयंतीलाल भंडारी

विगत 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संकट से चरमराती देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर बड़े आर्थिक पैकेज का एलान किया। अगले दिन वित्त मंत्री ने इस पैकेज के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें एमएसएमई (लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग) क्षेत्र की मदद पर जोर है। वित्त मंत्रालय के पिछले पैकेज और रिजर्व बैंक के कदमों को जोड़ दें, तो कुल पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का होगा, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 फीसदी के बराबर है।

नए आर्थिक पैकेज में ग्रामीण भारत, कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यमों, किसानों और मध्यवर्ग सहित सभी वर्गों पर खास ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पैकेज के जरिये आत्मनिर्भरता के पांच स्तंभों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

इनमें तेजी से छलांग लगाती अर्थव्यवस्था, आधुनिक भारत की पहचान बनता बुनियादी ढांचा, नए जमाने की तकनीक केंद्रित व्यवस्थाओं पर चलता तंत्र, देश की ताकत बन रही आबादी और मांग व आपूर्ति चक्र को मजबूत बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नया पैकेज न केवल अर्थव्यवस्था को गतिशील करेगा, वरन देश को आत्मनिर्भरता की नई डगर पर आगे बढ़ाता हुआ भी दिखाई देगा।

ऐसे में, देश की आत्मनिर्भरता में ग्रामीण भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देगी। वैश्विक अध्ययन रिपोर्टों में भी यह बात सामने आ रही है कि कोविड-19 का भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सबसे कम असर दिखेगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि यद्यपि कोरोना के कारण भारत की विकास दर में तेज गिरावट आएगी, पर विशाल खाद्यान्न भंडार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के लिए सहारा होंगे। एशियाई विकास बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के पास कृषि और खाद्यान्न जैसे मजबूत आर्थिक बुनियादी घटक है, जिनकी ताकत से यह अगले वित्त वर्ष में जोरदार आर्थिक वृद्धि करता दिखाई दे सकेगा। 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में कम प्रभावित हुआ था।

इसकी वजह थी देश के ग्रामीण बाजार की जोरदार ताकत। कोविड-19 के बीच फिर भारत के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्व दिखाई दे रहा है। महामारी का प्रसार रोकने के लिए जहां शहरी भारत का बड़ा हिस्सा

लॉकडाउन में है, वहीं ग्रामीण भारत के बड़े क्षेत्र को शीघ्रतापूर्वक लॉकडाउन से बाहर लाया गया।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान करीब 17 फीसदी है। पर देश के 60 फीसदी लोग खेती पर आश्रित हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है और शेष 50 फीसदी में छोटे-मंझोले उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान है।

कोविड-19 के बीच भारत का मजबूत पक्ष यह है कि देश के सामने 135 करोड़ लोगों की भोजन संबंधी चिंता नहीं है। अप्रैल अंत तक देश के पास करीब 10 करोड़ टन खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार सुनिश्चित हो गया है, जिससे करीब डेढ़ साल तक खाद्यान्न जरूरतें पूरी की जा सकती है।

यही नहीं, कृषि मंत्रालय द्वारा पेश 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में खाद्यान्न उत्पादन 29.19 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। जबकि आगामी फसल वर्ष 2020-21 में खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 29.83 करोड़ टन रखा गया है। अच्छे मानसून की संभावना न केवल कृषि जगत के लिए, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है।

लॉकडाउन में सरकार के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सराहनीय सक्रियता दिखाई दे रही है। किसानों को उनकी उपज मंडियों के अलावा सीधे बेचने की भी इजाजत दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पशुपालन और डेयरी उत्पादन को अहमियत दी गई है, तो रोजगार के सबसे बड़े स्रोत मनरेगा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा सिंचाई और जल संरक्षण योजनाओं को भी मनरेगा से जोड़ दिया गया है।

अच्छे मूल्यों पर फसल खरीदे जाने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। जो मजदूर गांव लौट गए हैं, वे कुछ महीनों तक गांवों में ही कृषि कार्य करेंगे। इससे खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की मांग बढ़ेगी। जन-धन खातों में नकदी डालने जैसे प्रयासों से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

कोरोना के कारण देश में किसानों द्वारा खेत तैयार करने, बुआई और फसल कटाई में मशीनों का अधिक प्रयोग, सरकार द्वारा गोदामों एवं शीतगृहों को बाजार का दर्जा दिया जाना, निजी मंडियां खोलने की अनुमति, कृषक उत्पादक संगठनों को मंडी की सीमा के बाहर लेन-देन की अनुमति, श्रम बचाने वाले उपकरणों के कारण कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण और फसल विविधीकरण जैसे जो सुधार दिखाई दे रहे हैं, यदि वे बाद में भी जारी रहे, तो कृषि क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा।

चुनौतियों के बीच हमें बाजार में आ रही रबी फसल के विपणन के लिए मौजूदा मंडी खरीद प्रणाली से

आगे बढ़कर सभी मार्केटिंग चैनल खोलने की रणनीति पर आगे बढ़ना होगा, ताकि सीधे किसान से खरीद भी हो सके। मनरेगा को न केवल कारगर ढंग से लागू किया जाए, बल्कि मजदूरी के लंबित भुगतान एवं काम मांगने पर काम दिलाने जैसी समस्याओं का भी समाधान निकाला जाए। ग्राम पंचायतों एवं सामुदायिक संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की अहमियत के बारे में स्पष्ट संदेश लगातार प्रसारित किए जाएं, ताकि ग्रामीण इलाकों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

उम्मीद करनी चाहिए कि कोविड-19 के संकट से देश को उबारने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित व्यापक आर्थिक पैकेज न केवल अर्थव्यवस्था को चरमराने से बचाएगा, वरन ग्रामीण भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर देश को आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ाएगा।

(यह लेख अमर उजाला से लिया गया है. लेखक प्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं अर्थशास्त्री हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं)

कोरोना काल में बैंकों की भांति और उपयोगी साबित हुए डाकघर

कपिल अग्रवाल

सरकार के लिए बोझ व जनता के लिए अनुपयोगी माने जा रहे और देश के समस्त डाकघरों की रौनक कोरोना काल में लौटती दिख रही है। बैंकों की भांति डाकघरों को तमाम नई सेवाओं व सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। सरकार ने इन्हें उपयोगी व कमाऊ बनाने के रास्ते खोज लिए हैं। करीब 1,900 करोड़ रुपये की एक परियोजना के तहत सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली बायोमैटिक हैंड मशीनें डाकियों को मुहैया कराई हैं जिनसे वे अब घर-घर जाकर मनीऑर्डर से लेकर जमा, निकासी आदि तमाम सुविधाएं आम जनता को देने लगे हैं।

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से लैस इन मशीनों से साधारण डाक, ई-मनीऑर्डर, स्पीड पोस्ट, बीमा प्रीमियम और अन्य ऐसे भुगतान जो बैंकों के माध्यम से किए जाते हैं समेत पैसा जमा करना व निकालना आदि आम जनता के लिए घर बैठे करना संभव हो चुका है। देश के समस्त डाकघरों को एकीकृत करने का काम शुरू हो चुका है और अब एक टोल फ्री नंबर द्वारा उक्त सेवाएं शुरू की जा रही हैं जिससे जनता घर बैठे अपने निकटतम डाकखाने से सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सके।

बैंकों का आधुनिकीकरण होने व कोरियर कंपनियों की अच्छी सेवाओं के चलते पिछले एक दशक से डाकखानों का महत्व व उपयोगिता लगभग खत्म होने लगी थी और एक समय इनको बंद करने की मांग उठने लगी थी। डाकघर बहुत ज्यादा घाटे में आ गए थे और इनके अस्तित्व पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। पर अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। हालांकि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उम्दा बुनियादी ढांचे का अभाव अभी भी कायम है और इसमें सुधार की उम्मीद फिलहाल कम ही प्रतीत हो रही है। सरकार ने डाकघरों में नेटवाकग व कंप्यूटरीकरण आदि का काम तो तेजी से आरंभ कर दिया है, किंतु प्रशिक्षण आदि व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया है। अभी तक डाकखानों में नोट गिनने और नकली नोटों की पहचान संबंधी मशीन भी नहीं लगाई गई है। बहरहाल नई हैंड मशीनों से न केवल डाक विभाग को, बल्कि आम जनता को भी घर बैठे तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। गांवों के लिए तो यह विशेष रूप से वरदान साबित हो रही है।

पहले जहां डाकघर से मनीऑर्डर भेजना बहुत दुष्कर व झंझट वाला कार्य था, वहीं अब ये बेहद आसान व सुगम हो गए हैं। इस योजना से भारतीय डाक विभाग आधुनिक ही नहीं बनेगा, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स कारोबार का फायदा भी उसे मिलेगा। अगर किसी सामान में कैश ऑन डिलीवरी यानी सामान पहुंचने के बाद ही रकम देने की शर्त है तो डाकिया मौके पर पैसा लेकर तत्काल ई-कॉमर्स कंपनियों के खाते में भेज देगा। इतना ही नहीं डाकिये की उस मशीन से किसी भी बैंक के खाते में जमा व निकासी की जा सकती है। इसके तहत डाकिये के साथ जो भी लेन-देन किया जाएगा, उसकी रसीद भी इस मशीन से फौरन निकल जाएगी। लेन-देन की जानकारी बीएसएनएल के मोबाइल नेटवर्क के जरिये डाक विभाग के मुख्य सर्वर पर फौरन भेज दी जाएगी।

हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। वह यह कि समुचित प्रशिक्षण, उपकरण व व्यवस्था के अभाव में कामकाज की गति बेहद धीमी है और आम जनता को भारी परेशानियों से दो-चार होना पड़ रहा है। डाकियों को ये नई मशीनें दे तो दी गई हैं, पर उन्हें इस बाबत प्रशिक्षित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ कंप्यूटराइजेशन व एकीकरण का काम पूरा न होने से ये मशीनें कई जगहों पर नकारा भी साबित हो रही हैं। चूंकि किसी भी डाकिये को यह मालूम नहीं होता कि डीलिंग वाले डाकघर में कंप्यूटराइजेशन व एकीकरण का काम पूरा हो गया है अथवा नहीं इसलिए मशीनों में ट्रांजेक्शन फंसने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम डाकघरों में शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है और जनता को सामान्य कामकाज निपटाने में भी कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

इसमें अधिकांश योगदान ई-कॉमर्स कंपनियों का है। कोरोना से पहले ई-कॉमर्स से कैश ऑन डिलीवरी मद की कमाई चालू वित्त वर्ष के अंत तक 2,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वित्त वर्ष के अंत तक मात्र 500 करोड़ रुपये ही था। अनुमान है कि अब विभाग की सेवाएं बेहतर होंगी और गड़बड़ी या सामान की चोरी की आशंका काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

(यह लेख दैनिक जागरण से लिया गया है, लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

कोरोना काल के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 50 हजार करोड़ डॉलर हो जाना सुखद आश्चर्य

▸ डॉ. सुशील कुमार सिंह

इन दिनों देश अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है। अर्थव्यवस्था की गाड़ी डगमगा गई है। मगर एक सुखद पहलू यह है कि कोरोना की बड़ी मार के बाद भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। देश में चौतरफा निराशाजनक स्थिति है और उदासीनता के परिवेश से सभी जकड़े हुए हैं। बावजूद इसके विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 50 हजार करोड़ डॉलर हो जाना एक सुखद आश्चर्य ही कहा जाएगा।

फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार की बढ़त के बीच भारत का बचा हुआ विकास दर यदि शीघ्र पटरी पर नहीं आता है तो बढ़त ले चुकी आर्थिक चुनौतियां देश में नाउम्मीदी का माहौल बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगी। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का एक फायदा यह होता है कि इससे सरकार और आरबीआइ को देश के बाह्य और आंतरिक आर्थिक मामलों को सुलझाने में कहीं अधिक मदद मिलती है।

गौरतलब है कि मई में विदेशी मुद्रा भंडार में 1,240 करोड़ डॉलर का उछाल आया और माह के अंत तक यह लगभग 50 हजार करोड़ डॉलर के पास पहुंच गया। रुपये में इसे लगभग 37 लाख करोड़ से अधिक कह सकते हैं।

वैसे कई लोग सोचते होंगे कि जब देश की माली हालत सबसे बड़े आर्थिक गिरावट में है, उद्योग-धंधे तथा सेवा क्षेत्र समेत छोटे-बड़े कारोबार कोरोना की चपेट में हैं तो ऐसे में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ रहा है।

जाहिर है इसका कोई आर्थिक कारण तो होगा। वैसे विदेशी मुद्रा भंडारण की बढ़त में भारत ही नहीं, बल्कि चीन भी इस मामले में सुखद स्थिति में है। गौरतलब है कि मई में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े से पता चलता है कि माह के अंत तक यहां यह भंडार 31 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया जो अप्रैल की तुलना में 0.3 फीसद बढ़त लिए हुए है।

हालांकि इन दिनों चीन कोरोना से राहत में है और भारत कोरोना के बीच उलझा हुआ है। ऐसे में भले ही चीन बढ़त में हो, पर भारत में मिल रही बढ़त उसकी बेहतरी का सूचक है। विदेशी मुद्रा भंडार आगामी एक वर्ष के आयात बिल के लिए शुभ संकेत दे रहा है। साथ ही इसकी बढ़त से यह भी संकेत मिलता है कि डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत होगा और भुगतान संतुलन के मामले में सकारात्मकता आएगी।

भारत की जीडीपी भारत के विकास का जरिया है और यहां की कुल जीडीपी में 15 प्रतिशत विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। इस मामले में यदि संतुलन बरकरार रहता है तो 15 फीसद वाला हिस्सा मजबूत रहेगा, लेकिन बाकी के 85 फीसद के लिए सरकार को एड़ी-चोटी का जोर लगाना ही होगा। विदेशी मुद्रा भंडार की बढ़त सभी समस्याओं का हल नहीं है लेकिन बढ़त ले चुकी समस्याओं का आनुपातिक हल जरूर है।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का प्रमुख कारण भारतीय शेयरों में विदेशी निवेश, साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जा रहा है। गौरतलब है कि विदेशी निवेशकों द्वारा अप्रैल और मई माह में कई भारतीय कंपनियों में रकम लगाई गई जो इसकी बढ़त का एक बड़ा कारण है। साथ ही भारतीय कंपनियोंपर इस कदम से विश्वास भी बढ़ता दिखाई देता है।

विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत पांचवें स्थान पर है और चीन पहले स्थान परा।कोरोना संकट से उपजी समस्या के चलते कई यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां चीन से विस्थापित होने का मन बना चुकी हैं और प्राथमिकता में भारत को भी देखा जा सकता है। ऐसे में भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए।

अमेरिका 19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ पहले तो चीन 13 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत लगभग तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है जो 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर के मसौदे पर आगे बढ़ रहा था, मगर गत एक तिमाही में सारे प्रयासों पर पानी फिर गया है। हालांकि कोरोना महामारी से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त थी। मूडीज की रिपोर्ट ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2 फीसद कर दिया है।

इतना ही नहीं, विकास दर को मौजूदा स्थिति के अंतर्गत ऋणात्मक होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। हालांकि मूडीज की रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2 फीसद होगी। यह तो आने वाला समय बताएगा पर आरबीआइ का संदर्भ भी विकास दर के मामले में कहीं अधिक गिरावट से युक्त देखा जा सकता है।

कोरोना का मीटर इन दिनों भारत में तेजी लिए हुए है और लॉकडाउन को लगभग समाप्त कर अनलॉक

को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार उखड़ती अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा मरहम है। विदेशी मुद्रा भंडार सोना और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर समेत विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों हेतु भारत द्वारा संचित एवं आरबीआइ द्वारा नियंत्रित की जाने वाली बाहरी संपत्ति है।

गौरतलब है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अधिकांश हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा संपत्तियों की ही है। जब संकट का समय आता है और उधार लेने की क्षमता घटने लगती है तो विदेशी मुद्रा आर्थिक तरलता को बनाए रखने में मददगार होती है। ऐसे में भुगतान संतुलन से लेकर कई आर्थिक संतुलन डगमगाने से पहले संभल जाते हैं।

(लेखक वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं)

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-23005850